

‘‘भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की स्थिति
का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन’’



इण्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ

मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम०ए०) समाजशास्त्र की उपाधि हेतु
प्रस्तुत
लघु शोध-प्रबन्ध

शोध निर्देशिका

वन्दना मिश्रा

असिस्टेन्ट प्रो०

इण्टीग्रल विश्वविद्यालय

लखनऊ

शोधकर्त्री

शालिनी वर्मा

एम०ए० (समाजशास्त्र) चतुर्थ सेमेस्टर

अनुक्रमांक : 2000102382

मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय

संस्थान

इण्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ

2021-22

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2021-22 में मास्टर ऑफ आर्ट्स एम0ए0(समाजशास्त्र) के लघु शोध-प्रबन्ध के रूप में **शालिनी वर्मा** ने “**भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन**” विषय पर शोध कार्य मेरे निर्देशन में पूर्ण मनोयोग से सम्पन्न किया है। प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध शोधकर्त्री का मौलिक कार्य है।

मैं प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध को एम0ए0 (समाजशास्त्र) की उपाधि के लिए सर्वथा उपयुक्त मानती हूँ।

निर्देशिका
वन्दना मिश्रा
असिस्टेन्ट प्रो०
मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय
इण्टीग्रल विश्वविद्यालय
लखनऊ

घोषणा-पत्र

मैं **शालिनी वर्मा** घोषणा करती हूँ कि मेरा यह शोधकार्य जिसका विषय “भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन” जो पूर्णतया मौलिक है। मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार इस विषय पर शोधकार्य कहीं भी किसी अन्य के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

शोध पर्यवेक्षिका

वन्दना मिश्रा
असिस्टेन्ट प्रो०
मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय
इण्टीग्रल विश्वविद्यालय
लखनऊ

शोधकर्त्री

शालिनी वर्मा
एम० ए०,(समाजशास्त्र) चतुर्थ सेमेस्टर
अनुक्रमांक : 2000102382

आभार

जिस करुणामयी ने मुझे जन्म दिया तथा जिनके ममत्वपूर्ण लालन पालन एवं अनुशासन में पलकर यह मानव जीवन पल्लवित हुआ है ऐसे में अपनी माता एवं पिता के चरणों में सर्वप्रथम प्रणति अर्पित करते हुए स्वयं को धन्यतम् अनुभव कर रही हूँ।

मैं आभारी हूँ अपनी शोध निर्देशिका असिस्टेन्ट प्रोफेसर वन्दना मिश्रा जी की जिनके मार्ग निर्देशन में यह लघु शोध प्रबन्ध पूर्ण हो सका।

साथ ही मैं अपने विश्वविद्यालय के मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय के समस्त प्राध्यापक एवं प्राध्यापिका जनों की जो हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में हमें निरन्तर दिशानिर्देशित करते रहे हैं।

अतः आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ।

मैं अपने सहपाठी मित्रों का भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। जिनकी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से मैं इस शोधकार्य को पूर्ण करने में सफल रही हूँ।

शालिनी वर्मा

एम०ए०, (समाजशास्त्र) चतुर्थ सेमेस्टर

अनुक्रमांक : 2000102382

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
अध्याय—प्रथम	9—37
परिचय	9
महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समझने के लिए प्रमुख सैद्धांतिक मॉडल	12
महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समझने का एक सैद्धांतिक आधार पारिस्थितिक मॉडल है:	12
लैंगिक आधारित हिंसा के स्तर	15
लैंगिक—आधार हिंसा के प्रकार	13
महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा	16
महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा	17
लैंगिक आधारित हिंसा के कारण	20
लैंगिक आधारित हिंसा के प्रभाव	21
लैंगिक आधारित हिंसा का वैश्विक परिदृश्य:	22
लैंगिक आधारित हिंसा का भारतीय परिदृश्य:	23
महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान	25
लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल:	25
लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय पहल:	27
वर्मा समिति की रिपोर्ट:	27
महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करना:	30

सतत परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता, सहयोग और क्षमता की आवश्यकता	30
प्राचीन भारत में स्त्रियाँ	32
वैदिक और उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियाँ	32
पौराणिक काल में स्त्रियाँ	33
मध्य काल में स्त्रियाँ	33
औद्योगिककरण	34
शिक्षा का विस्तार	34
महिलाओं के अधिकार	34
सामाजिक विधान	35
सामाजिक अधिकारों की चेतना	35
सामाजिक उपचार	36
आर्थिक उपचार	36
आर्थिक विधान	37
राजनैतिक अधिकार	37
द्वितीय – अध्याय	38–54
साहित्यिक समीक्षा	38
अध्ययन का स्वरूप	38
सम्बन्धित साहित्य का अर्थ	38
सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के प्रमुख पाँच कार्य	38
सम्बन्धित साहित्य की आवश्यकता :	39

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से लाभ	40
सम्बन्धित साहित्य के स्रोत	40
तृतीय – अध्याय	55–63
अनुसंधान क्रियाविधि	56
अध्ययन की कार्य प्रणाली	56
अनुसंधान की अर्थ व परिभाषा	56
अनुसंधान क्रियाविधि	59
अध्ययन का उद्देश्य:	57
अध्ययन की रूपरेखा:	60
अध्याय—चतुर्थ	64–82
भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की स्थिति	64
महिलाओं का उत्पीड़न	64
दहेज से संबंधित हत्याएं	67
विधाओं के विरुद्ध हिंसा	69
हिंसा के शिकार	70
हिंसा के अपराधकर्ता	71
क्या हम आज के युग	72
हिंसा के प्रकार	72
घरेलू हिंसा के मामलों वाले प्रमुख राज्य	72
घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों में सबसे कम प्रतिशत वाले राज्य	73

उत्तर प्रदेश में हिंसा	74
महिलाओं के खिलाफ अपराध पर घटनाएं	76
यौन हिंसा का अनुभव	77
पंचम अध्याय	83—94
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005	87
कार्यान्वयन में बाधाएं	87
संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन	89
षष्ठम – अध्याय	95—99
निषकर्ष एवं सुझाव	95
सुझाव	98
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	100

अध्याय—प्रथम

परिचय

दुनिया भर में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों, सभी जातियों, धर्मों और राष्ट्रीयताओं की महिलाओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अनुभव किया जाता है। जिसमें पुरुषों की भूमिका दखी जा सकती है। यह आज दुनिया में मानवाधिकारों का सबसे व्यापक उल्लंघन है। इसके रूप सूक्ष्म और स्पष्ट दोनों हैं और विकास पर इसका प्रभाव गहरा है। और यह दुनिया भर की संस्कृतियों में इतनी गहराई से अंतर्निहित है कि यह लगभग अदृश्य है।

हिंसा शब्द लैटिन शब्द विज़ से निकला है, जिसका अर्थ है बल और दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक श्रेष्ठता का उपयोग करने और बाधा की धारणाओं को संदर्भित करता है। हिंसा उत्परिवर्ती है, क्योंकि यह बहुत अलग समय, स्थानों, परिस्थितियों और वास्तविकताओं से प्रभावित होती है। हिंसा को सहन किया जाता है और निंदा की जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर हिंसा मौजूद है, अगर मानव जाति, अलग, तेजी से जटिल और एक ही समय में अधिक खंडित और स्पष्ट रूप धारण करती है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा लिंग आधारित हिंसा को परिभाषित करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को इस प्रकार समझा जाना चाहिए: “लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ित होने की संभावना है, जिसमें ऐसी धमकी भी शामिल है। कार्य, जबरदस्ती या मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करना, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में हो”।

परिभाषा को घोषणा के अनुच्छेद 2 में बढ़ाया गया है, जो तीन क्षेत्रों की पहचान करता है जिनमें केवल हिंसा होती है:

1. परिवार में होने वाली शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा, जिसमें मारपीट भी शामिल है; घर में महिला बच्चों का यौन शोषण; दहेज से संबंधित हिंसा; वैवाहिक बलात्कार; महिला जननांग विकृति और महिलाओं के लिए हानिकारक अन्य पारंपरिक प्रथाएं; गैर-जीवनसाथी हिंसा; और शोषण से संबंधित हिंसा;

2. शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा जो सामान्य समुदाय के भीतर होती है, जिसमें बलात्कार भी शामिल है; यौन शोषण; काम पर, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जगहों पर यौन उत्पीड़न और धमकी; महिलाओं की तस्करी; और जबरन वेश्यावृत्ति;

3. शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा, जहां कहीं भी होती है, राज्य द्वारा की जाती है या उसे माफ कर दिया जाता है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं पर वर्चस्व और भेदभाव किया गया है और महिलाओं की पूर्ण उन्नति को रोका गया है।”

सभी समाजों में, गरीबी, भेदभाव, अज्ञानता और सामाजिक अशांति महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सामान्य भविष्यवक्ता हैं। फिर भी एक महिला की गरिमा और सुरक्षा के सबसे स्थायी दुश्मन पुरुष प्रभुत्व और महिला अधीनता को बनाए रखने के उद्देश्य से सांस्कृतिक ताकतें हैं—अक्सर आदरणीय परंपरा के नाम पर बचाव किया जाता है। पूरे जीवन चक्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक पैटर्न, कुछ पारंपरिक या प्रथागत प्रथाओं के हानिकारक प्रभावों और जाति, लिंग, भाषा या धर्म से जुड़े चरमपंथ के सभी कृत्यों से उत्पन्न होती है जो परिवार में महिलाओं को निम्न स्थिति को कायम रखती हैं, कार्यस्थल, समुदाय और समाज।

विकासशील देशों में, महिलाओं के खिलाफ हिंसक प्रथाओं को अक्सर सांस्कृतिक बुनाई की किस्में के रूप में मान्यता दी जाती है और उनका बचाव किया जाता है। उदाहरण के लिए, पत्नी की पिटाई को कई देशों में प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है – गीतों, कहावतों और शादी समारोहों में मनाया जाने वाला एक मर्दाना विशेषाधिकार। पति का अपनी पत्नी को पीटने या शारीरिक रूप से डराने का अधिकार कई समाजों में एक गहरी मान्यता है। . यहां तक कि महिलाएं भी अक्सर कुछ शर्तों के तहत एक निश्चित मात्रा में शारीरिक शोषण को उचित मानती हैं। हिंसा का औचित्य लैंगिक मानदंडों से उपजा है – रिश्तों में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में विकृत विचार।

उत्पीड़न, मारपीट और यौन हमले के खतरे से मुक्ति एक ऐसी अवधारणा है जिसके बारे में ज्यादातर महिलाओं को कल्पना करना मुश्किल होता है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाज के ताने-बाने में इस हद तक बुना जाता है कि पीड़ित कई महिलाओं को लगता है कि उनकी गलती है। . हिंसा को अंजाम देने वालों में से कई मजबूत सामाजिक संदेशों द्वारा उचित महसूस करते हैं जो कहते हैं कि बलात्कार, पिटाई, यौन उत्पीड़न, बाल शोषण और हिंसा के अन्य रूप स्वीकार्य हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की मीडिया में छवियां, जो बलात्कार या यौन दासता के साथ-साथ महिलाओं और लड़कियों के यौन वस्तुओं के रूप में उपयोग को दर्शाती हैं, जिसमें पोर्नोग्राफी भी शामिल है, ऐसी हिंसा के निरंतर प्रसार में योगदान देने वाले कारक हैं, जो बड़े पैमाने पर समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, बच्चे और युवा।

हिंसा का अनुभव या खतरा दुनिया भर में लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है, सभी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक वर्गों में, धन, जाति, धर्म और संस्कृति की सीमाओं को पार करते हुए, इस प्रकार महिलाओं के समाज में पूरी तरह से भाग लेने के अधिकार को बाधित करता है। हर प्रकार की हिंसा सभी महिलाओं को धमकाती है और अपने जीवन के बारे में चुनाव करने की उनकी क्षमता को सीमित करती है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिलाओं द्वारा उनके मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के आनंद का उल्लंघन करती है और उन्हें कम करती है या समाप्त करती है। शारीरिक हिंसा लगभग हमेशा मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के साथ होती है, जो अपमानजनक और अपमानजनक हो सकती है। हिंसा के कृत्य या धमकी, चाहे वह घर के भीतर हो या समुदाय में हो, या राज्य द्वारा किया गया हो या माफ किया गया हो, महिलाओं के जीवन में भय और असुरक्षा पैदा करता है और समानता की उपलब्धि और विकास और शांति के लिए बाधाएं हैं। हिंसा का डर महिलाओं की गतिशीलता पर एक स्थायी बाधा है और संसाधनों और बुनियादी गतिविधियों तक उनकी पहुंच को सीमित करता है। व्यक्ति और समाज के लिए उच्च सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक लागत महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़ी हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन महत्वपूर्ण सामाजिक तंत्रों में से एक है जिसके द्वारा महिलाओं को पुरुषों की तुलना में एक अधीनस्थ स्थिति में लाने के लिए मजबूर किया जाता है।

20वीं शताब्दी में आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के सारांश में ग्रह पर सभी लोगों के लिए न्यूनतम मानवाधिकारों के प्रस्ताव और परिभाषाएं शामिल हैं, जो निस्संदेह महिलाओं के खिलाफ लिंग हिंसा की पहचान और जांच को प्रभावित करती हैं। ये सम्मेलन थे: संयुक्त राष्ट्र का चार्टर (1945), नरसंहार पर कन्वेंशन (1948); नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा (1966); आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार (1966); नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (1965); महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (1979); अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ सम्मेलन (1984); बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (1989); और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम, सजा और उन्मूलन पर अंतर-अमेरिकी सम्मेलन – बेलेम दो पारा का सम्मेलन (1994) (3)। इन सम्मेलनों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की उन्नत समझ और उन्मूलन के लिए सकारात्मक नतीजों के साथ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे की स्थापना की।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समझने के लिए प्रमुख सैद्धांतिक मॉडल:

महिलाओं के खिलाफ उनके अंतरंग भागीदारों द्वारा की गई हिंसा का विश्लेषण पारिस्थितिक मॉडल के माध्यम से किया जा सकता है, जो व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध की व्याख्या करता है। इस हिंसा के प्रति लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण सहायता कार्यक्रम स्थापित करने की दृष्टि से किया जाना चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समझने का एक सैद्धांतिक आधार पारिस्थितिक मॉडल है:

यह प्रस्ताव विभिन्न लेखकों के काम पर आधारित है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अध्ययन करने और जानने की दृष्टि से "एक एकीकृत पारिस्थितिक ढांचे" का प्रस्ताव करता है। पारिस्थितिक मॉडल चार अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय कारकों का अध्ययन करता है: व्यक्ति, परिवार, सामुदायिक और सामाजिक-सांस्कृतिक, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। यह मॉडल अपने विशिष्ट स्तरों के बीच बातचीत में हिंसा पर केंद्रित है। ये कार्य-कारण के स्तर को बढ़ा रहे हैं, जिसमें न केवल एक निर्धारक है, बल्कि संचालन

कारकों की एक बातचीत है, जो हिंसा का पक्ष लेती है या इसके खिलाफ व्यक्ति की रक्षा करती है। इन कारण कारकों और उनकी अंतःक्रियाओं को उनके विशिष्ट संदर्भों और सांस्कृतिक वातावरण में जानने की आवश्यकता है। यह ज्ञान हिंसा की रोकथाम और विशिष्ट हस्तक्षेप (8) में आगे बढ़ने के लिए नाजुक बिंदुओं और सड़कों की पहचान करने में मदद करता है।

पहला स्तर जैविक और व्यक्तिगत इतिहास कारकों की पहचान करता है। ट्रेस करने योग्य डेटा में व्यक्तिगत और जनसांख्यिकीय विशेषताएं (आयु, लिंग, शिक्षा, आय), आक्रामक या आत्म-अवमूल्यन व्यवहार के पूर्ववृत्त, मानसिक या व्यक्तित्व विकार और पदार्थ संबंधी विकार शामिल हैं।

दूसरे स्तर में घनिष्ठ संबंध शामिल हैं, जैसे कि जोड़ों और भागीदारों के बीच, परिवार के अन्य सदस्यों और दोस्तों के बीच। यह देखा गया है कि इनसे पीड़ित होने या हिंसक कृत्यों को अंजाम देने का खतरा बढ़ जाता है। हिंसक कृत्यों को करने या उकसाने वाले मित्र होने से यह जोखिम बढ़ सकता है कि युवा लोग इन कार्यों को भुगतेंगे या निष्पादित करेंगे।

तीसरा स्तर उन सामुदायिक संदर्भों की पड़ताल करता है जहां सामाजिक संबंध विकसित होते हैं, जैसे कि स्कूल, कार्य स्थल और पड़ोस। इन वातावरणों की विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वे हिंसक कृत्यों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। जोखिम निवास स्थान की गतिशीलता, जनसंख्या घनत्व, उच्च बेरोजगारी स्तर और क्षेत्र में नशीली दवाओं के यातायात के अस्तित्व जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है।

चौथा स्तर समाज की संरचना से संबंधित सामान्य कारकों पर निर्देशित है। ये कारक एक ऐसा माहौल बनाने में योगदान करते हैं जो हिंसा को उकसाता है या रोकता है, जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक मानकों के कारण हथियार प्राप्त करने की संभावना। इनमें ऐसे मानक शामिल हैं जो अपने बच्चों की भलाई पर माता-पिता के अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं, आत्महत्या को एक व्यक्तिगत विकल्प के रूप में देखते हैं, न कि हिंसा के एक रोके जाने योग्य कार्य के रूप में, महिलाओं और लड़कों पर पुरुषों के प्रभुत्व की पुष्टि करते हैं, नागरिकों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक उपयोग का समर्थन करते हैं या राजनीतिक

संघर्षों का समर्थन करते हैं। इस स्तर में अन्य तथ्य भी शामिल हैं, जैसे स्वच्छता, आर्थिक, शिक्षाप्रद और सामाजिक नीतियां, जो समूहों के बीच आर्थिक या सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने में योगदान करती हैं।

विभिन्न स्तरों पर कारक एक दूसरे को कैसे सुदृढ़ या संशोधित करते हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, एक आक्रामक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति एक परिवार या समुदाय के अंदर हिंसक रूप से कार्य करेगा जो हिंसा के माध्यम से संघर्षों को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह अधिक शांत वातावरण में होने की तुलना में अधिक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तेजी से सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार, शीघ्र पता लगाने और प्रभावी हस्तक्षेप कार्यक्रम स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्मुखीकरण, कानूनी सलाह, शिक्षाप्रद और कार्य प्रशिक्षण प्रदान करते हुए पीड़ित सहायता और सुरक्षा सेवाओं की एक व्यापक पेशकश है। इनमें से कुछ वैकल्पिक सेवाओं को विकसित करते हैं, जो हमलावरों पर निर्देशित होती हैं, क्योंकि शारीरिक हिंसा विभिन्न आयु समूहों में आर्थिक, रुग्णता और मृत्यु दर पर प्रभाव डालती है।

यह ढांचा इंगित करता है कि हिंसा एक महिला के जीवन के सभी क्षेत्रों में मौजूद हो सकती है और अपने मूल्यांकन चक्र (शारीरिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा और सामाजिक हिंसा) के माध्यम से खुद को विभिन्न रूपों और परिस्थितियों में प्रकट कर सकती है। इसे धर्मों और सरकारों द्वारा मानकों और संहिताओं के माध्यम से प्रबलित किया जाता है। कई विशेषज्ञ हिंसा का विश्लेषण करते हैं और वे सभी इस बात से सहमत हैं कि यह घटना महिलाओं की अखंडता को खराब करती है, जिससे खराब विकृत स्वास्थ्य, पारिवारिक और सामाजिक समूह में विकार पैदा होते हैं।

महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए परिणामों में, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जटिलताएं सामने आती हैं, जो महिलाओं में महत्वपूर्ण अक्षमताएं पैदा करती हैं, उन सामाजिक परिणामों को भूले बिना, जो कभी-कभी उनके लिए इस हिंसक घर को छोड़ना असंभव बना देते हैं जहां उनकी व्यक्तिगत गारंटी का उल्लंघन होता है और उनके व्यक्तित्व को बदनाम किया जाता है। चूंकि यह घटना लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और इसका सभी स्तरों

(क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे निर्धारकों और कारकों की तलाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जो हिंसा की घटना की बेहतर समझ की ओर ले जाते हैं, जो इस पर कई महिलाओं को प्रभावित करता है। ग्रह। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीखा व्यवहार, पुरुष के हिंसक व्यवहार और महिला के निष्क्रिय व्यवहार के बीच संबंध को स्पष्ट करने की उम्मीद करते हुए, हिंसा को समझने के लिए पारिस्थितिक मॉडल की सिफारिश की है। सहायता कार्यक्रम स्थापित करने की दृष्टि से हिंसा के प्रति लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

लैंगिक आधारित हिंसा के स्तर:

लैंगिक आधारित हिंसा के तीन स्तर हैं। ये घर या परिवार स्तर, सामुदायिक स्तर और राज्य स्तर हैं।

घर के भीतर हिंसा: घरेलू हिंसा लिंग आधारित हिंसा का सबसे प्रचलित रूप है। यह आमतौर पर तब होता है जब कोई पुरुष अपनी महिला साथी की पिटाई करता है। मनोवैज्ञानिक शोषण हमेशा शारीरिक शोषण के साथ होता है और अधिकांश महिलाओं को उनके साथी द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है जो कई बार दुर्व्यवहार करती हैं। एक जोड़े और परिवार में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा में यौन शोषण, महिला जननांग विकृति और महिलाओं और लड़कियों के लिए हानिकारक अन्य पारंपरिक प्रथाएं, वैवाहिक बलात्कार, दहेज से संबंधित हिंसा, अनाचार, गैर-पत्नी हिंसा शामिल हैं। जैसे एक बेटे का अपनी मां के खिलाफ हिंसा और शोषण से संबंधित हिंसा और आजादी से वंचित करना। लैंगिक आधारित हिंसा पर उपलब्ध इन आंकड़ों के बावजूद, कुछ देशों में लैंगिक आधारित हिंसा पर कोई सटीक जानकारी नहीं है। नाइजीरिया जैसे अधिकांश देशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में चुप्पी की संस्कृति व्याप्त है, जिससे इसकी सीमा की सही तस्वीर प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। सटीक लेखा-जोखा प्राप्त करना कठिन होने के कुछ कारण यह है कि अधिकांश लिंग-आधारित हिंसा निजी क्षेत्र में होती है – परिवारों के भीतर, घरों के अंदर, और दृष्टि से बाहर।

सामान्य समुदाय के भीतर महिलाओं के खिलाफ हिंसा: सामान्य समुदाय के भीतर होने वाली शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा में बलात्कार, यौन उत्पीड़न और स्कूल या काम में धमकी, जबरन उपचार और अपमानजनक दवा, महिलाओं के शरीर का शोषण और व्यावसायीकरण शामिल हैं। बढ़ी हुई गरीबी से संबंधित है जो मुख्य रूप से बेलगाम आर्थिक उदारवाद का परिणाम है। सामान्य समुदाय के भीतर होने वाली इस प्रकार की हिंसा में महिलाओं पर बाधाओं या बल द्वारा लगाए गए गर्भनिरोधक, जबरन नसबंदी या गर्भपात, कन्या भ्रूण का चयनात्मक गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या (महिलाओं का विश्व मार्च, 2000) शामिल हैं।

राज्य द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा: शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा अक्सर राज्यों द्वारा की जाती है या सहन की जाती है जो मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान पर परंपरा या परंपरा को प्राथमिकता देते हैं। कुछ देशों में, धार्मिक कट्टरवाद का उदय महिलाओं के उनकी आर्थिक स्वायत्तता के अधिकार और उनकी पसंद की स्वतंत्रता के बारे में बेहद परेशान करने वाला है। महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार इतना बढ़ा है कि यह रंगभेद के एक नए रूप का गठन करता है। महिलाओं को दूसरे वर्ग की प्राणी माना जाता है, कम मूल्य की, अपने मौलिक अधिकारों से वंचित। सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को युद्ध के हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके कई रूप हैं जिनमें हत्या, बलात्कार, यौन दासता, बंधक बनाना और जबरन गर्भधारण (महिलाओं का विश्व मार्च, 2000) शामिल है।

सलामी (2000) में उद्धृत कुमारस्वानी ने मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के कुछ अतिरिक्त उल्लंघनों की पहचान की, जैसे कि यौन व्यापार के लिए महिलाओं और लड़कियों की तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, बलात्कार, यौन शोषण और यौन पर्यटन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधों का केंद्र बन गए हैं।

लैंगिक-आधार हिंसा के प्रकार:

1. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा दुनिया भर में अभी तक छिपी हुई समस्या है। यह विकसित और विकासशील देशों में समान रूप से होता है। आज करोड़ों महिलाओं के लिए

घर आतंक का ठिकाना है। घर पर मारपीट महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अब तक का सबसे सार्वभौमिक रूप है और प्रजनन आयु की महिलाओं के लिए चोट का एक महत्वपूर्ण कारण है। 2000 यूनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया की आधी से अधिक महिला आबादी घरेलू हिंसा के अधीन है। वास्तव में, घरेलू हिंसा दुखद रूप से आम जगह है लेकिन यह बंद दरवाजों के पीछे होती है और पीड़ित के डर से बोलने लगता है। यहां तक कि अमेरिका जैसे तुलनात्मक रूप से खुले समाज में भी, शोध से पता चलता है कि 100 में से केवल 1 पीड़ित महिला ही अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करती है।

दुनिया भर में करोड़ों लड़कियां और महिलाएं दुर्बल करने वाली और अक्सर घातक मानवाधिकारों के हनन को झेलती हैं। उनके जन्म के दिन से ही लड़कियों का अवमूल्यन और अपमान किया जाता है, लिंग के रंगभेद में फंस जाते हैं। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में दासता को समाप्त किए जाने के लंबे समय बाद, कई समाज अभी भी महिलाओं के साथ संपत्ति की तरह व्यवहार करते हैं: उनकी बेड़ियों में खराब शिक्षा, आर्थिक निर्भरता, सीमित राजनीतिक शक्ति, प्रजनन नियंत्रण तक सीमित पहुंच, कठोर सामाजिक परंपराएं और कानून की नजर में असमानता है। इन बेड़ियों को बनाए रखने के लिए हिंसा एक प्रमुख साधन है।

महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा:

महिलाओं का यौन शोषण किसी भी रूप में अनेक रूप धारण कर लेता है। सबसे विकृत और अपमानजनक रूप बलात्कार है। शारीरिक बल के प्रयोग या धमकी के द्वारा किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किए गए संभोग को कभी-कभी जबरन बलात्कार कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से, किसी व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब पीड़िता को वश में करने के लिए बल प्रयोग किया गया हो। अधिकांश समाज बलात्कार की अपनी परिभाषा के हिस्से के रूप में या कम से कम, बलात्कार के सबसे गंभीर रूप के रूप में बल का उपयोग बरकरार रखते हैं। हालांकि, कुछ समाजों ने इस पारंपरिक आवश्यकता को संशोधित किया है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का बलात्कार करता है जिसे वह जानता है, तो इसे या तो परिचित बलात्कार या डेट रेप कहा जाता है। दो लोग दोस्त, पूर्व प्रेमी या वर्तमान में डेटिंग कर सकते हैं। अध्ययनों से संकेत

मिलता है कि किसी अजनबी या रिश्तेदार की तुलना में किसी परिचित द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार होने की संभावना अधिक होती है। जान-पहचान वाला जबरन रेप कर सकता है। हालाँकि, परिचित बलात्कार शब्द आमतौर पर तब लागू होता है जब संभोग गैर-सहमतिपूर्ण होता है, लेकिन इसमें आमतौर पर जबरन बलात्कार से जुड़े शारीरिक बल शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि हमला या हिंसा की धमकी। सभी महिलाओं के डर में, बलात्कार का डर सबसे काला है। चिंतित माता-पिता अपनी बेटियों को बचपन से ही अनजान पुरुषों से बात न करने की चेतावनी देकर बलात्कार की धमकी के लिए परोक्ष संकेत देते हैं।

किसी व्यक्ति के पति या पत्नी के बलात्कार को वैवाहिक बलात्कार या पति-पत्नी का बलात्कार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध जो सहमति की उम्र तक नहीं पहुंचा है, वैधानिक बलात्कार के रूप में जाना जाता है। संभोग के लिए सहमति की आयु राज्य के कानून के आधार पर भिन्न होती है, लेकिन किसी भी राज्य की तुलना में अधिक नहीं होती है। अधिकांश राज्य कानूनों के तहत, पीड़ित जितना छोटा होता है, सजा उतनी ही अधिक होती है।

बलात्कार को "सेक्स का कार्य नहीं बल्कि प्राथमिक हथियार के रूप में सेक्स के साथ हिंसा का कार्य" के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक बलात्कारी कहता है, "मैं महिलाओं का बलात्कार क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं मूल रूप से, एक पुरुष के रूप में, एक शिकारी हूँ और सभी महिलाएं शिकार की तरह पुरुषों को देखती हैं। मैं एक महिला के चेहरे पर अभिव्यक्ति के बारे में कल्पना करता हूँ जब मैं उसे 'पकड़' लेता हूँ और वह महसूस करती है कि वह बच नहीं सकती। ऐसा लगता है कि मैं जीत गया, मैं उसका मालिक हूँ। बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। "बलात्कार युद्ध की दुर्घटना नहीं है, या सशस्त्र संघर्ष के लिए एक आकस्मिक सहायक नहीं है। संघर्ष के समय में इसका व्यापक उपयोग दर्शाता है यह महिलाओं के लिए अद्वितीय आतंक रखता है, यह अद्वितीय शक्ति बलात्कारी को अपने शिकार पर देता है, और यह अद्वितीय अवमानना के 22 परिचय पीड़ितों के लिए प्रदर्शित करता है। संघर्ष में बलात्कार का

उपयोग उन असमानताओं को दर्शाता है जो महिलाएं अपने दैनिक जीवन में शांतिकाल में सामना करती हैं।

व्यावसायिक यौन शोषण: दुनिया के कुछ विकासशील देशों में, ज्यादातर लड़कियों को सेक्स टूरिज्म की आड़ में वेश्यावृत्ति के लिए बनाया जाता है। यूनिसेफ दस्तावेज़ के अनुसार सेक्स पर्यटन तब होता है जब अमीर लोग छुट्टियों के दौरान दुनिया के उन्नत देशों से ब्राजील, डोमिनिकन गणराज्य और थाईलैंड आदि जगहों पर 13 से 15 साल के बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए यात्रा करते हैं। 2000 के आसपास, सीएनएन ने एक एशियाई देश में सेक्स टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित किया, जहां पर्यटक यात्रा करते थे और उन होटलों में जाते थे जहां युवा लड़कियों ने अमीर पर्यटकों की यौन इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें नग्न सेवा दी थी। यह अधिनियम बच्चों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है और यह महिलाओं के खिलाफ एक वास्तविक हिंसा है।

सलामी (2000) के अनुसार, नेपाल कालीन कारखाने नियोक्ताओं द्वारा यौन अन्वेषण के साथ-साथ भारतीय वेश्यालयों के लिए भर्ती केंद्र भी हैं। सलामी के अनुसार भारतीय वेश्यालयों की फैक्ट्रियों में 50% से अधिक श्रमिक बच्चे हैं। उनके अनुसार, नाइजीरिया के ईदो राज्य में, लड़कियों के यौन शोषण का व्यवसाय माता-पिता की मंजूरी से किया जाता है ताकि वे जल्दी से अमीर हो सकें। सलामी के अनुसार व्यवसाय (2000)

नाइजीरिया और उत्तरी अफ्रीका दोनों में एक सिंडिकेट शामिल है जो लड़कियों को व्यावसायिक यौन कार्य करने के लिए इटली ले जाता है। महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार की हिंसा पीड़ितों को काफी शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाती है। वे श्वसन रोगों, यौन संचारित संक्रमणों, अवांछित गर्भधारण और नशीली दवाओं की लत सहित कई स्वास्थ्य जोखिमों के संपर्क में हैं।

लैंगिक आधारित हिंसा के कारण

लिंग आधारित हिंसा के कारण हिंसा के प्रकार के आधार पर कई और विविध हैं। दुनिया भर में महिलाओं के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण हिंसा को बनाए रखने में मदद करता है। रूढ़िवादी भूमिकाएँ जिसमें महिलाएं पुरुषों के अधीन होती हैं, एक महिला की उन विकल्पों को चुनने की क्षमता को बाधित करती हैं जो उसे दुर्व्यवहार को समाप्त करने में सक्षम बनाती हैं।

नजेंगा (1999), जो केन्या में साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, ने केन्या में महिलाओं के साथ लिंग आधारित हिंसा में वृद्धि के कारणों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कारण काफी विविध हैं। कारणों में से एक वह स्थान है जिसमें लोग रहते हैं। जितने अधिक भीड़-भाड़ वाले लोग होंगे, नजेंगा ने टिप्पणी की, उतनी ही अधिक घरेलू हिंसा होने की संभावना है। नजेंगा (1999) ने निष्कर्ष निकाला कि गरीबी, जो यह भी निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति कहाँ और कैसे रहता है, योगदान करने वाले कारकों में से एक है।

वित्तीय असुरक्षा लिंग आधारित हिंसा का एक अन्य कारण है। नजेंगा (1999:6) ने टिप्पणी की कि यदि कोई व्यक्ति बौद्धिक या आर्थिक रूप से अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता है, तो वह शारीरिक रूप से ऐसा करेगा। एक अन्य कारण समाज द्वारा बनाई गई छवि है जो एक पुरुष को मजबूत, शिक्षित, रचनात्मक और चतुर के रूप में देखा जाता है जबकि एक महिला इन सभी लक्षणों के विपरीत है। माता-पिता जिस तरह से अपने बच्चों का लालन-पालन करते हैं, जो लड़के और लड़कियों के बीच असमानता पैदा करता है, वह भी बाद के जीवन में लिंग आधारित हिंसा का एक स्रोत है। जब कोई लड़का बड़ा हो जाता है, यह जानते हुए कि उसे अपने कपड़े धोने, खाना बनाने या घर में मदद करने के लिए नहीं है, अगर वह बड़ा हो जाता है और उस घर से आने वाली महिला से शादी कर लेता है जहां लड़कियों और लड़कों के बीच कर्तव्यों को समान रूप से साझा किया जाता है, यह तनाव पैदा कर सकता है जिससे हिंसा हो सकती है।

बिटांगारो (1999:9) ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों को संक्षेप में बताया था कि जिस तरह से समाज की स्थापना की गई है, उसमें गहराई से निहित है—सांस्कृतिक विश्वास, शक्ति संबंध, आर्थिक शक्ति असंतुलन और पुरुष प्रभुत्व का मर्दाना विचार।

लैंगिक आधारित हिंसा के प्रभाव

लैंगिक आधारित हिंसा के प्रभाव विनाशकारी और लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। वे एक महिला के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं और एक उत्तरजीवी को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और पारस्परिक रूप से डरा सकते हैं। एक महिला जो घरेलू हिंसा का अनुभव करती है और अपने साथी के साथ अपमानजनक संबंध में रहती है, उसे गर्भवती होने के लिए मजबूर किया जा सकता है या उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात हो सकता है, या उसका साथी जानबूझकर उसे यौन संचारित संक्रमण के लिए उजागर कर सकता है।

बिटांगारो (1999:9) ने बताया कि एक बाल मनोवैज्ञानिक कहता है कि "हिंसा का बच्चों पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है..." एक बच्चा जो हिंसा से गुज़रा है या देखा है, वह एक तरफ पीछे हट सकता है, चिंतित या उदास हो सकता है; दूसरी ओर, बच्चा आक्रामक हो सकता है और छोटे भाई-बहनों पर नियंत्रण कर सकता है।

लड़के आमतौर पर आक्रामक व्यवहार करते हैं और वयस्कों के रूप में, अपने जीवनसाथी को हरा सकते हैं। यौन शोषण का प्रभाव शक्ति का शोषण है। युवा लोग विशेष रूप से जोखिम में हैं और इसका उनके यौन और उत्पादक स्वास्थ्य के लिए स्थायी परिणाम हो सकते हैं। लागत में अवांछित गर्भधारण, यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई), शारीरिक चोट और आघात शामिल हो सकते हैं। बिटांगारो (1999) ने बताया कि युगांडा में दुनिया के कई हिस्सों की तरह, एक महिला के साथ बहुत अधिक कलंक जुड़ा हुआ है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है। फीमेल जेनिटल कटिंग (FGC) के प्रभाव कई हैं। युगांडा (1998) में महिलाओं की दृष्टि की रिपोर्ट के अनुसार, काटने वाले सर्जन बूढ़ी महिलाएं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन महिलाओं का दावा है कि उनके पास पुश्तैनी शक्तियां हैं। महिला जननांग काटने को एक लड़की के यौन आनंद में बाधा के रूप में देखा जा सकता है। महिलाओं

की दृष्टि (1998) की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों को तीव्र दर्द, रक्तस्राव, पेट में दर्द, मासिक धर्म, संक्रमण या आघात का अनुभव करने के लिए जाना जाता है।

जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो (2000) ने विश्व बैंक को यह कहते हुए रिपोर्ट किया कि लैंगिक आधारित हिंसा 15 साल की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य पर भारी बोझ है—जैसा कि एचआईवी, तपेदिक और बच्चे के जन्म के दौरान संक्रमण, कैंसर और हृदय रोगों से होता है। महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन ने कार्रवाई के लिए एक मंच अपनाया है, जो घोषित करता है कि "महिलाओं के खिलाफ हिंसा समानता, विकास और शांति के उद्देश्य की उपलब्धि में बाधा है" (जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो 2000: 3)।

लैंगिक आधारित हिंसा का वैश्विक परिदृश्य:

लैंगिक आधारित हिंसा, जो महिलाओं की भलाई, अधिकारों और गरिमा के लिए खतरा है, हाल ही में क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सीमाओं तक फैले एक वैश्विक मुद्दे के रूप में सामने आई है। राज्य के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में लगभग 18% महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य विकसित देशों जैसे डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम आदि में स्थिति है बेहतर नहीं। यू.एस. में, न्याय विभाग ने बताया कि, हर साल; 3– 4 मिलियन महिलाओं को उनके पति या पार्टनर द्वारा पस्त किया जाता है। स्वीडन में भी, जो लैंगिक –संबंधी सूचकांक में उच्च स्थान पर है, 1996 में महिलाओं पर हिंसा के 18650 रिपोर्ट किए गए मामलों में से 66% घरेलू हमले के थे। इसके अलावा 1996 में इंग्लैंड और वेल्स में दर्ज 681 में से 681 अपराधों में से 45% महिलाओं को उनके जीवनसाथी या प्रेमियों द्वारा मार डाला गया था। (जोशी 2002)।

विकासशील देशों जैसे एंटीगुआ, बारबाडोस, कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, श्रीलंका और अन्य के डेटा से महिलाओं पर शारीरिक और यौन शोषण के व्यापक प्रसार का पता चलता है। घरेलू हिंसा समूह (1993) द्वारा किए गए जापान की 796 महिलाओं के एक अध्ययन में 59% ने शारीरिक शोषण, 66% भावनात्मक शोषण और 60% ने यौन शोषण की सूचना दी। अफ्रीकी देशों, केन्या, युगांडा और तंजानिया के अध्ययनों से पता

चलता है कि 42% महिलाओं को उनके घरों में शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। चीन में, 57% महिलाओं में पत्नी को पीटने का एक निर्णायक सबूत बताया गया है। (जोशी 2002)

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर मानवाधिकारों और कन्वेंशन की सार्वभौमिक घोषणा (सीईडीएडब्ल्यू) महिलाओं के लिए कुछ विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों को लागू करती है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि केवल 44 देशों में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून हैं। केवल 17 देशों ने वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक अपराध बनाया है और केवल 27 देशों ने यौन उत्पीड़न पर कानून पारित किया है। (अमीन 2002)

लैंगिक आधारित हिंसा का भारतीय परिदृश्य:

पोषित नारीत्व, जिसकी लंबे समय से प्रशंसा की जाती रही है, विदेशी और आधुनिक संस्कृति की आमद से दूर हो गई थी। वर्षों से, सांसारिक गतिविधियों ने अधिकतम अनुपात पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण पारंपरिक संस्कृति लुप्त होती जा रही है। दुल्हन को जलाने, दहेज हत्या, प्रताड़ना, क्रूरता आदि जैसे हृदय विदारक कृत्यों से परिवार की सुख-शांति छीन ली गई है। यहां तक कि महिला भ्रूण को भी आत्महत्या के लिए प्रताड़ित किया जाता है। कन्या का अधिकार हमेशा खतरे में रहता है। क्योंकि कन्या के रूप में जन्म लेना ही समाज के कुछ वर्गों द्वारा अभिशाप माना जाता है। सदी की जनगणना के मोड़ पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं जबकि 2001 में यह आंकड़ा प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थीं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 0 – 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 में केवल 927 लड़कियां हैं। पंजाब जैसे कुछ भारतीय राज्यों में यह अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 793 लड़कियों जितना कम है। (शर्मा 2001)

अपने घरों और कार्यस्थलों में सत्ता और पदानुक्रम के गलत पक्ष पर रखे जाने के कारण, महिलाओं को अक्सर हिंसा का शिकार होना पड़ता है। पुलिस के रिकॉर्ड महिलाओं के खिलाफ अपराध के रिपोर्ट किए गए मामलों का विवरण प्रदान करते हैं, लेकिन अधिकांश हिंसा की रिपोर्ट नहीं की जाती है। वास्तव में, महिलाओं को अपने रक्षकों के हाथों हिंसा

का सामना करना पड़ता है। 90 के दशक के दौरान दर्ज किए गए डेटा से पता चलता है कि 1999 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में वर्ष 1989 की तुलना में लगभग 102% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर दशक के दौरान 68699 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई। उपलब्ध डेटा पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय दंड संहिता और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत दर्ज मामलों के लिए एक बढ़ती प्रवृत्ति को इंगित करता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में, यातना में 278% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि बलात्कार की घटनाओं में 69% की वृद्धि हुई और उसके बाद 24% छेड़छाड़ की गई। 1995 से 1999 की अवधि के दौरान यौन उत्पीड़न में लगातार 86% की वृद्धि दर्ज की गई।

बलात्कार के मामलों में 1989 में 9150 से 1999 में 15468 तक तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इस खोज की अधिक परेशान करने वाली विशेषता यह है कि 27% पीड़ित नाबालिग थे। हालांकि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध देश में सबसे कम रिपोर्ट किए गए अपराधों में से एक हैं, खुद के लिए बोलते हैं। यह तर्क दिया गया है कि बच्चों के खिलाफ दर्ज किए गए प्रत्येक मामले के लिए सौ हैं, जो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं।

1997 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के रूप में योग्य पांच कारक निर्धारित किए। ये शारीरिक संपर्क या अग्रिम, यौन एहसान के लिए एक मांग या अनुरोध, यौन रूप से रंगीन टिप्पणी, अश्लील साहित्य दिखाना और अन्य अवांछित शारीरिक, और मौखिक या गैर मौखिक यौन आचरण हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों द्वारा बलात्कार पीड़ितों की जांच नहीं करने की प्रथा के खिलाफ अपनी कड़ी अस्वीकृति दर्ज की है, जब तक कि पुलिस ने उन्हें मामले को आगे नहीं बढ़ाया। यह देखा गया है कि डॉक्टर के इस रवैये से पीड़ित की जांच में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप सबूत या तो धुल गए या खो गए। (सत्यसुंदरम 2002)।

महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिए सशक्त बनाता है ताकि उनके द्वारा सामना किए जाने वाले संचयी सामाजिक आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक नुकसान को बेअसर किया जा सके। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति करना है। भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकार उपकरणों की भी पुष्टि की है। उनमें से प्रमुख 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव (सीईडीएडब्ल्यू) के उन्मूलन पर कन्वेंशन का अनुसमर्थन है।

लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल:

संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के समय से ही महिलाओं की उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना मौलिक मानव अधिकारों में, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य में, पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास की पुष्टि करने के लिए एक बुनियादी लक्ष्य के रूप में निर्धारित करती है। 1946 में महिलाओं के मुद्दों से निपटने के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग की स्थापना की गई थी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने भेदभाव की अस्वीकार्यता के सिद्धांत की पुष्टि की थी और घोषणा की थी कि सभी इंसान स्वतंत्र और समान सम्मान और अधिकारों और अधिकारों में पैदा हुए हैं और हर कोई किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है, लिंग के आधार पर भेद सहित। हालांकि, मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ काफी भेदभाव मौजूद रहा क्योंकि महिलाओं और लड़कियों को समाज द्वारा लगाए गए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, न कि कानून द्वारा। इसने अधिकारों की समानता और मानवाधिकारों के सम्मान के सिद्धांत का उल्लंघन किया। 7 नवंबर, 1967 को महासभा ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर एक घोषणा को अपनाया, और

घोषणा में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने के लिए, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर एक सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू) अपनाया गया। इस कन्वेंशन को अक्सर महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में वर्णित किया जाता है। इसने अधिकारों का एक व्यापक सेट निर्धारित किया है जिसके लिए महिलाओं सहित सभी व्यक्ति हकदार हैं, महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अतिरिक्त साधन हैं। उपरोक्त सम्मेलन के अलावा, संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (1976– 1985) के दौरान मैक्सिको सिटी (1975), कोपेनहेगन (1980) और नैरोबी (1985) में तीन सम्मेलन आयोजित किए गए थे। चौथा सम्मेलन 1995 में बीजिंग में आयोजित किया गया था, जिसने महिलाओं की चिंताओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता को काफी बढ़ाया है। बीजिंग सम्मेलन ने कहा कि "महिला अधिकार मानव अधिकार हैं" और इसने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मानवाधिकार निकायों के काम में महिलाओं के मानवाधिकारों के एकीकरण का आह्वान किया। इसने सार्वजनिक और निजी जीवन में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को मानवाधिकारों के मुद्दों के रूप में माना। सम्मेलन ने महिलाओं के अधिकारों और हानिकारक प्रभावों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष के उन्मूलन का आह्वान किया। 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के मुद्दों पर प्रगति का आकलन करने के लिए 'महिला: लैंगिक समानता, विकास और 21वीं सदी के लिए शांति' पर एक विशेष सत्र बुलाया। फरवरी 2005 में, महिलाओं की स्थिति पर आयोग ने अपने 49वें सत्र में महिला मानवाधिकार समझौते पर हुई प्रगति को देखा, जिसे 15 बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के रूप में जाना जाता है। सम्मेलन ने गरीबी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मानवाधिकार, शक्ति और निर्णय लेने और बालिकाओं सहित कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। 2005 में, महासभा के तेईसवें विशेष सत्र को विश्व शिखर सम्मेलन के परिणाम के रूप में दोहराया गया था। शिखर सम्मेलन ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और प्रेरक लैंगिक भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लिया। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की बैठक 14 मार्च, 2011 को आर्थिक और सामाजिक परिषद चैंबर में विश्व में लैंगिक हिंसा के वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए हुई थी।

लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय पहल:

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग: जनवरी 1992 में, सरकार ने महिलाओं के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने के लिए एक विशिष्ट जनादेश के साथ इस वैधानिक निकाय की स्थापना की, जहां आवश्यक हो, संशोधन का सुझाव देने के लिए मौजूदा कानून की समीक्षा करें।

(ii) स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण: संसद द्वारा 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई सुनिश्चित करते हैं।

(iii) बालिका के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (1991–2000): कार्य योजना बालिकाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के अंतिम उद्देश्य के साथ बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करना है।

(iv) महिला अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय नीति, 2001: मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2001 में "महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति" तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य है महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण 26.

(v) महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन, 2010: मार्च 2010 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण विकास है जो वर्तमान सरकार के हस्तक्षेपों के समन्वित मूल्यांकन और भविष्य के प्रोग्रामर्स को इसके साथ संरेखित करने के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा। एमपीईडब्ल्यू के नुस्खे को हकीकत में बदलें। मिशन 2011–12 के दौरान परिचालित किया गया था।

वर्मा समिति की रिपोर्ट:

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा जिसे यौन अपराधों के लिए कानूनों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था, ने जनवरी 2013 के दौरान सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों और अत्याचारों से

निपटने के लिए आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव की सिफारिश की है जो निम्नानुसार हैं: बलात्कार के लिए सजा: पैनल ने नहीं किया है बलात्कारियों के लिए मौत की सजा की सिफारिश की। यह सुझाव देता है कि बलात्कार के लिए सश्रम कारावास या आरआई को सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होनी चाहिए। यह अनुशंसा करता है कि मृत्यु या "लगातार वानस्पतिक अवस्था" के लिए सजा 20 वर्ष से कम की अवधि के लिए आरआई होनी चाहिए, लेकिन जीवन के लिए भी हो सकती है, जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष जीवन होगा। सामूहिक बलात्कार, यह सुझाव देता है कि कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए, जिसे आजीवन भी बढ़ाया जा सकता है और सामूहिक बलात्कार के बाद मौत की सजा दी जानी चाहिए। अन्य यौन अपराधों के लिए सजा: पैनल ने सभी प्रकार के यौन अपराधों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को पहचाना और सिफारिश की – दृश्यरतिकता को सात साल तक की जेल की सजा दी जाए; तीन साल तक किसी भी माध्यम से बार-बार पीछा करना या किसी व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करना। एसिड हमलों के लिए सात साल तक की सजा होगी अगर कारावास; तस्करी पर आरआई के साथ सात से दस साल तक की सजा दी जाएगी। शिकायत दर्ज करना और चिकित्सा जांच: बलात्कार की हर शिकायत पुलिस द्वारा दर्ज की जानी चाहिए और नागरिक समाज को अपने संज्ञान में आने वाले बलात्कार के किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है, "कोई भी अधिकारी, जो बलात्कार का मामला दर्ज करने में विफल रहता है, या उसकी जांच को रोकने का प्रयास करता है, वह अपराध करता है जो निर्धारित अनुसार दंडनीय होगा।" यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की चिकित्सीय जांच के लिए प्रोटोकॉल का भी सुझाव दिया गया है। पैनल ने कहा, "इस तरह के प्रोटोकॉल आधारित, पेशेवर चिकित्सा परीक्षा समान अभ्यास और कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है।" विवाहों का पंजीकरण होना चाहिए: प्राथमिक अनुशंसा के रूप में, भारत में सभी विवाह (व्यक्तिगत कानूनों के बावजूद जिनके तहत ऐसे विवाह किए जाते हैं) अनिवार्य रूप से एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पंजीकृत होने चाहिए।

मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि विवाह बिना दहेज की मांग के संपन्न हो गया है और यह दोनों भागीदारों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति से हुआ है। दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन: पैनल ने कहा, "जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों को मान्यता दी जा सकती

है, वह तभी प्रकट हो सकती है जब उनके पास न्याय तक पूर्ण पहुंच हो और जब कानून के शासन को उनके पक्ष में बरकरार रखा जा सके। "पैनल का सुझाव है कि प्रस्तावित आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2012 को संशोधित किया जाना चाहिए। "चूंकि पुरुषों के साथ-साथ समलैंगिक, ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल बलात्कार पर यौन हमले की संभावना एक वास्तविकता है, प्रावधानों को उसी के बारे में संज्ञान लेना चाहिए," यह कहता है। विकलांग व्यक्तियों को बलात्कार से बचाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया, और ऐसे व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं, पैनल ने कहा कि "तत्काल आवश्यकता" थी। 17 महिलाओं के अधिकारों का विधेयक: महिलाओं के लिए एक अलग अधिकार विधेयक जो एक महिला को सम्मान और सुरक्षा का जीवन देता है और यह सुनिश्चित करेगा कि एक महिला को अपने संबंधों के संबंध में पूर्ण यौन स्वायत्तता का अधिकार होगा। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की समीक्षा: पैनल ने देखा है कि "सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम द्वारा व्यवस्थित यौन हिंसा की छूट को वैध बनाया जा रहा है।" इसने कहा है कि जल्द से जल्द क्षेत्रों में थैट। (सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम) को जारी रखने की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसने संघर्ष क्षेत्रों में महिला सुरक्षा के लिए विशेष आयुक्तों को तैनात करने की भी सिफारिश की है। पुलिस सुधार: जनता के विश्वास को प्रेरित करने के लिए, पैनल ने कहा, "उत्कृष्ट क्षमता और चरित्र की प्रतिष्ठा वाले पुलिस अधिकारियों को पुलिस बल के उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिए।" यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस बल में अपेक्षित नैतिक दृष्टि है, सभी मौजूदा नियुक्तियों की समीक्षा की जानी चाहिए। पैनल ने दृढ़ता से सिफारिश की कि "कानून प्रवर्तन एजेंसियां राजनीतिक आकाओं के हाथों में उपकरण न बनें।" इसने कहा, "पुलिस बल के प्रत्येक सदस्य को समझना चाहिए कि उनकी जवाबदेही केवल कानून के प्रति है और किसी और के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन में नहीं है।" न्यायपालिका की भूमिका: संवैधानिक उपायों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। न्यायपालिका इस तरह के मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में गहराई से संबंधित होने पर स्वतः संज्ञान ले सकती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक अखिल भारतीय रणनीति उचित होगी। न्यायिक पक्ष पर उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश गुमशुदा बच्चों के अवैध व्यापार आदि पर अंकुश लगाने के लिए उचित

आदेश देने पर विचार कर सकते हैं। राजनीतिक सुधार: न्यायमूर्ति वर्मा समीति ने कहा कि राजनीति के अपराधीकरण से निपटने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। पैनल ने सुझाव दिया है कि, यदि आपराधिक अपराध के मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, तो उम्मीदवार को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जो किसी आरोप का खुलासा करने में विफल रहता है, उसे बाद में अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसने सुझाव दिया कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सांसदों, जो पहले ही संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुने जा चुके हैं, को स्वेच्छा से अपनी सीटें खाली कर देनी चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करना:

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को संबोधित करना एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती है। दुनिया भर में हिंसा की दर अकेले दर्शाती है कि अभी तक कोई सही या आसानी से महसूस होने वाला समाधान नहीं है। हालांकि, विश्व स्तर पर और क्षेत्रीय रूप से, अनुसंधान वर्तमान में उभर रहा है जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा (ओडीई, 2008; एसवीआरआई, 2014; डब्ल्यूएचओ और एलएसएचटीएम, 2010) को संबोधित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता के कठोर साक्ष्य को संश्लेषित करता है। यह शोध सफल और आशाजनक दृष्टिकोणों की कई सुसंगत विशेषताओं पर प्रकाश डालता है:

उपयुक्त, सतत परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता, सहयोग और क्षमता की आवश्यकता है:

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की समस्या के उचित, स्थायी समाधान के लिए उस संदर्भ में हिंसा की व्यापकता और विशेषताओं की विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है जिसमें समस्या का अनुभव होता है। स्थानीय समुदायों, महिलाओं और संगठनों के साथ साझेदारी में काम करना, जिनके पास अंतरंग ज्ञान है, और इस बारे में नवीन विचार हैं कि हिंसा को कैसे संबोधित किया जाए, यह एक मूलभूत आवश्यकता है। सामूहिक प्रतिबद्धता पर निर्मित सहयोगात्मक, बहुक्षेत्रीय भागीदारी के सफल होने की सबसे अधिक संभावना है। भारत-प्रशांत संदर्भ में नागरिक समाज संगठनों और सरकारी संस्थानों का स्थानीय क्षमता निर्माण आवश्यक है। समस्या का समाधान करने की प्रतिबद्धता को

दीर्घकालिक, महत्वपूर्ण वित्तीय, मानव और तकनीकी संसाधनों (ओडीई, 2008; एसवीआरआई, 2014; डब्ल्यूएचओ और एलएसएचटीएम, 2010) के साथ समर्थित होना चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा घरेलू और सार्वजनिक, शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो सकती है। महिलाओं के मन में हिंसा का भय बना रहता है जिसके कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी का अभाव हो जाता है। महिलाओं के मन में हिंसा का डर इतना गहरा हो गया है कि समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को पूरी तरह से हटाने के बाद भी आसानी से बाहर नहीं किया जा सकता है

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की जड़ें लिंग आधारित भेदभाव और सामाजिक मानदंडों और लैंगिक रूढ़ियों में निहित हैं जो इस तरह की हिंसा को कायम रखती हैं। महिलाओं पर हिंसा के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए, प्रयासों ने मुख्य रूप से उत्तरजीवियों के लिए प्रतिक्रियाओं और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके मूल और संरचनात्मक कारणों को संबोधित करके इसे पहले स्थान पर होने से रोका जाए।

देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा भारी आवाज के साथ लगातार और खतरनाक रूप से होती जा रही है। यह हर नागरिक के कंधों पर दबाव और भारी जिम्मेदारी पैदा कर रहा है। हालांकि, सभी अधिकारों को समझने और लाभ लेने के लिए महिलाओं को सशक्त और खुद के लिए जिम्मेदार होने की तत्काल आवश्यकता है।

सम्मानजनक संबंधों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले युवा लड़कों और लड़कियों के साथ शिक्षित और काम करके रोकथाम जीवन में जल्दी शुरू होनी चाहिए। लिंग आधारित हिंसा को रोकने और मिटाने के लिए युवाओं के साथ काम करना तेज, निरंतर प्रगति के लिए एक "सर्वश्रेष्ठ शर्त" है। जबकि सार्वजनिक नीतियां और हस्तक्षेप अक्सर जीवन के इस चरण की अनदेखी करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण समय होता है जब लैंगिक समानता के आसपास के मूल्य और मानदंड जाली होते हैं।

प्राचीन भारत में स्त्रियाँ

प्राचीन भारत में स्त्रियाँ की स्थिति से संबंधित दो तरह के पैचारिक सम्प्रदाय मिलते हैं। एक सम्प्रदाय का कहना है कि स्त्रियाँ “पुरुषों के बराबर” थीं, जबकि दूसरे सम्प्रदायों की मान्यता है कि स्त्रियाँ को न केवल अपमान ही होता था बल्कि उनके प्रति घृणा भी की जाती थी। दोनों ही सम्प्रदायों ने अपने दृष्टिकोण की पुष्टि में धार्मिक साहित्य से उदाहरण दिए हैं। आपस्तम्ब ने निर्दिष्ट किया था: “जब स्त्री रास्ते में जा रही हो तो सभी उसे रास्ता दें”। हम जिनका सम्मान करते हैं उनके साथ यही व्यवहार करते हैं, अतः यह दर्शाता है कि स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। मनु ने कहा था: “जहाँ स्त्रियों की दुर्दशा होती है वहाँ सम्पूर्ण परिवार विनाश को प्राप्त होता है, किन्तु जहाँ वे सुखी हैं वहाँ परिवार सदैव समृद्धि को प्राप्त करता है।” याज्ञवल्क ने भी कहा है: “स्त्रियाँ पृथ्वी पर समस्त देवीय गुणों का प्रतीक हैं सोम ने अपनी समस्त नवित्रता उन्हें प्रदान की है, गान्धर्व ने मृदु वाणो तथा अग्नि ने उन्हें अत्यन्त आकर्षक बनाने के लिए अपनी समस्त चमक उन पर न्योछावर कर दी है।” स्त्रियों के विषय में इतने ऊँचे आदर्श रामायण एवं महाभारत में भी स्थान स्थान पर दोहराए गए हैं। महाभारत काल में स्त्रियाँ न केवल गृहस्थ जीवन का केन्द्र थी बल्कि समस्त सामाजिक संगठन की आधार बिंदु थी। ऐसी आशा की जाती थी कि पुरुष अपनी पत्नी की इच्छा के आगे नतमस्तक होगा तथा उसकी सेवा व पूजा करेगा।

वैदिक और उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियाँ

वैदिक एवं उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति का निर्धारण इस तथ्य से पता किया जा सकता है कि उनको कितनी स्वतंत्रता प्राप्त थी तथा उन पर किस सीमा तक प्रतिबन्ध लगे हुए थे। वैदिक तथा रामायण – महाभारत (महाकाव्य) काल में स्त्रियाँ कभी पर्दा नहीं करती थीं। उन्हें अपने जीवन साथी के वरण में स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी, यद्यपि विवाह-विच्छेद की अनुमति उन्हें प्राप्त नहीं थी। पुरुषों को भी यह अनुमति प्राप्त नहीं थी। घर में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और उन्हें अर्द्धांगिनी माना जाता था। महाभारत में कहा गया था, “मृदु भाषी पत्नियाँ सुख में अपने पति की मित्र होती हैं, धार्मिक कृत्यों के समय वे उनके पिता के समान होती हैं तथा दुःख व कष्ट के समय वे उनकी माता के समान होती हैं।” गृहस्थ जीवन में स्त्रियाँ सर्वोपरि होती थीं। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति

पूर्णरूपेण असहायों की स्थित नहीं थीं, बल्कि उनकी स्थित एक ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो न्याय एवं औचित्य से प्रेरित थी।

आर्थिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे न कहीं नौकरी करती थीं और न धन अर्जन क्योंकि उनके लिए यह आवश्यक नहीं था। घर उत्पादन का केन्द्र था; वस्त्र बनाने का काम घर पर ही होता था। स्त्रियां कृषि कार्यो में भी अपने पति की सहायता करती थीं। कुछ स्त्रियां अध्यापन कार्य में भी व्यक्त होती थीं।

पौराणिक काल में स्त्रियाँ

पौराणिक काल में स्त्रियाँ की स्थित में कमी आयी। (हिन्दू समाज में धार्मिक ग्रन्थों का ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार से है: वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, गृह—सूत्र, धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ, रामायण व महाभारत और पुराण) सामाजिक क्षेत्र में, पूर्व यौन परिपक्व विवाह का प्रचलन प्रारम्भ हुआ, विधवा विवाह का निषेध होने लगा, पति को स्त्री के लिए भगवान का स्तर दिया जाने लगा, स्त्रियों के लिए शिक्षा का पूर्ण निषेध प्रारम्भ हुआ, सती प्रथा प्रचलन में आई, पर्दा प्रथा प्रारम्भ हुई, तथा बहुपत्नी प्रथा व्यवहार में स्वीकार की जाने लगी। “एक पत्नी और गुलाम सम्पत्ति के अधिकारी नहीं होते, मान्यता के आधार पर स्त्री को उसके पति की सम्पत्ति में भाग से वंचित कर दिया गया। धार्मिक क्षेत्र में स्त्री को बलिदान भेंट करने से, प्रार्थना से, हट योग से तथा तीर्थ यात्रा करने से वंचित कर दिया गया।

मध्य काल में स्त्रियाँ

भारत पर मुसलमानों का प्रथक आक्रमण आठवीं शताब्दी में हुआ, जिस काल में शंकराचार्य जीवित थे। शंकराचार्य के नेतृत्व में हिन्दू समाज बढ़ते हुए बौद्ध धर्म का सामना करने की विधियां खोजने में व्यस्त था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से वेदों की उत्कृष्टता पर पुनः बल दिया और वेदों में स्त्रियों को समानता का अधिकार प्राप्त था। ग्यारहवीं शताब्दी में पुनः महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की।

औद्योगिकरण

ब्रिटिश काल के अर्थिक परिवर्तन बड़े निर्णायक थे। मशीनी उद्योगों के विकास और हस्तशिल्प का विनाश दोनों ने ही स्त्री व पुरुषों की आजीविका पर गंभीरतम आघात किया। अंग्रेजों द्वारा विकसित की गई अर्थिक संरचना देश-भक्ति या जन हित के लिए नहीं की गई थी। मूलतः शासक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए ही देश के संसाधनों का दोहन किया गया था।

शिक्षा का विस्तार

स्त्रियों को शिक्षा दिये जाने का विचार ब्रिटिश शासन काल में उदय हुआ। इससे पूर्व यह एक सार्वभौमिक मान्यता थी कि स्त्रियों को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें आजीविका का अर्जन नहीं करना है। भक्ति आन्दोलन के बाद ईसाई मिशनरियों ने स्त्रियों की शिक्षा रूचि लेना प्रारम्भ किया। 1824 में सबसे पहली बार लड़कियों का स्कूल बम्बई में प्रारम्भ हुआ।

स्कूल में अध्ययनरत प्रत्येक 100 लड़कियों में से 62 प्राइमरी स्तर पर, 26 मिडिल स्तर पर, तथा 12 हाई स्कूल स्तर पर अध्ययनरत हैं; अतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इन विविध स्तरों पर अध्ययनरत लड़कियों की संख्या कम है, फिर भी यह स्पष्ट है कि 1941 के बाद से लड़कियों की संख्या में प्रत्येक स्तर पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

महिलाओं के अधिकार

ऐसे समाज में जहाँ कुल जनसंख्या की आधी तथा तीन-पंचमांश भाग अशिक्षित महिलाएं हैं (1991 जनगणना), ऐसे रूढ़िवादी परम्पराओं एवं विश्वासों तथा प्रथाओं में जकड़े हुए समाज को रातों रात नहीं बदला जा सकता। न ही इनके विरुद्ध प्रबल जनमत तैयार करना होता है।

पुरुषों के समान स्त्रियों को भी भारतीय संविधान द्वारा प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं, समानता का अधिकार, अर्थात् अवसरों की समानता, कानून के समक्ष समानता, कानूनों का समान संरक्षण तथा नौकरियों आदि में लिंग के आधार पर भेदभाव न समझा जाना।

1. स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात् भाषण की स्वतंत्रता निवास की स्वतंत्रता एवं व्यवसाय व गतिशीलता की स्वतंत्रता।

2. शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, अर्थात् बेगार के विरुद्ध।
3. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात् उपदेश तथा धर्म का स्वतंत्रतापूर्वक अनुपालन।
4. सम्पत्ति का अधिकार, अर्थात् सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने का अधिकार।
5. सांस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, अर्थात् संस्कृति का संरक्षण तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार।

सामाजिक विधान

महिलाओं से संबंधित तथा सामाजिक कानूनों से संबंधित चार प्रमुख मामले हैं, विवाह गोद लेना संरक्षकता एवं गर्भपात विवाह से संबंधित प्रमुख समस्याएं हैं, (1) जीवन साथी का चुनाव, (2) विवाह की आयु, (3) बहु पत्नी विवाह, (4) नियोग्य विवाह, (5) निष्भावी विवाह, (6) विवाह विच्छेद, (7) दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन (8) गुजारा भत्ता, (9) बच्चे का संरक्षण (10) देहज (11) पुनर्विवाह।

इस अनुसंधान का सिद्धान्तिक मॉडल यह था कि किसी विशेष क्षेत्र में जैसे, सामाजिक, राजनैतिक, अर्थिक व धार्मिक महिलाओं की अधिकार चेतना का स्तर चार बातों पर निर्भर करता है। स्त्री की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि (शैक्षिक स्तर, आकांक्षाओं का स्तर और व्यक्तिगत आवश्यकता) उसकी सामाजिक परिस्थितियाँ (रिश्तेदारी की अपेक्षाएं, पति के आदर्श, तथा परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण), उसका अपना दृष्टिकोण (अपने स्तर तथा भूमिका के प्रति) तथा उसका अर्थिक आधार (वर्ग-सदस्यता का स्तर) हमारे विप्लेषण में विभिन्न प्रकार के अधिकारों के प्रति चेतना तथा अधिकारों के उपभोग के संतुष्ट स्तर से संबंधित निम्नलिखित तथ्य सामने आए

सामाजिक अधिकारों की चेतना

- महिलाओं को विवाह संबंधी कानूनों की जानकारी बहुत कम है। हमारे सर्वेक्षण में केवल दस में से एक महिला को ही अपने जीवन साथी के चुनाव के अधिकार की जानकारी थी, लगभग 50 में से एक को विवाह की सही आयु की जानकारी थी, पांच में से भी कम को तलाक के अधिकार का ज्ञान था, दस में से एक से भी कम को तलाक के बाद गुजारे भत्ते के अधिकार का ज्ञान था, पांच में से एक से कम

को विधवा, पुनर्विवाह अधिकार का और पांच में से एक से भी कम को दहेज कानून का ज्ञान था। इन सभी पक्षों को एक साथ रखने पर हम कह सकते हैं कि दस में से एक को ही विवाह कानूनों की कुछ जानकारी थी।

- परिवार में निर्णय लेने के विषय में महिलाओं की भूमिका किनारे की होती है। पत्नि के साथ पति महत्वहीन विषया को लेकर सलाह करते हैं।
- पति पत्नी के बीच दाम्यत संबंधों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो सका है।
- लगभग दो तिहाई महिलाओं अपने वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन से संतुष्ट होती हैं।
- घर में काम से संतुष्ट का स्तर आयु, शिक्षा तथा आय के साथ साथ बदलता रहता है।

सामाजिक उपचार

सामाजिक उपचारों में महिला कल्याण सेवाएं, ऐच्छिक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन तथा जन संचार माध्यमों द्वारा महिलाओं का कानूनी प्रशिक्षण आदि सम्मिलित हैं। ऐच्छिक संगठनों को ऐसी महिलाओं का पता लगाने का कार्य करना है जिन्हें इस प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता है।

जन शिक्षा एवं जागृति कार्यक्रम स्त्रियों की सहायता अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के उद्देश्य से कर सकते हैं तथा सेवा संस्थाओं का सहयोग उनके अधिकारों के दिलाने के लिए लिया जा सकता है।

आर्थिक उपचार

शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण महिलाओं को कार्य ढूंढने के योग्य बनाएंगे जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकेगी। आर्थिक स्वतंत्रता से तनाव कम होगा, उनके आदर्शों में मूल रूप से परिवर्तन आएगा और वे अपने अधिकारों तथा मागों के प्रति अधिक साहसपूर्वक खड़ी हो सकेगी।

आर्थिक विधान

आर्थिक विधान से संबंधित विषय है : सम्पत्ति का अधिकार समान पारिश्रमिक, कार्य करने की दशाएं , प्रसूति लाभ, तथा कार्य सुरक्षा। एक महिला के सम्पत्ति अधिकार का अर्थ है उसका पत्नी, पुत्री, विधवा तथा माँ के रूप में सम्पत्ति का अधिकार।

एक विधवा को भी अपने मृत पति की सम्पत्ति में से उसके पुत्रों और पुत्रियों के बराबर का भाग मिलता है। इस विधान ने स्त्रीधन एवं गैर स्त्रीधन के बीच का भेद भी समाप्त कर दिया है।

जहाँ तक समान पारिश्रमिक का संबंध है, समान पारिश्रमिक अधिनियम महिला तथा पुरुष कर्मियों के पारिश्रमिक में भेद करने की अनुमति नहीं देता। जो मालिक इन विधानों का पालन नहीं करते उन के लिए दण्ड का प्रावधान है।

राजनैतिक अधिकार

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं को दो प्रमुख अधिकार हैं: महिलाओं को मताधिकार और विधान मण्डल के लिए योग्यता। महिला मताधिकार की माँग सर्वप्रथम 1917 में की गई थी, किन्तु साउथ बरो फ्रेन्चाइज कमेटी ने 1918 में इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 1919 में सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया कि वे स्त्री मताधिकार के संबंध में अपने अलग विधान लागू करें।

1935 के भारत सरकार अधिनियम में शैक्षिक योग्यता के आधार पर स्त्री मताधिकार प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के बाद स्त्री मतदाताओं की संख्या तथा राज्य विधान मण्डलो तथा लोक सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

द्वितीय – अध्याय

साहित्यिक समीक्षा

अध्ययन का स्वरूप :

किसी अच्छे नियोजित अनुसंधान अध्ययन से पहले सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अति आवश्यक है। सर्वेक्षण शोधकर्ता का जिस क्षेत्र में वह अनुसंधान करने वाला है उसमें वर्तमान ज्ञान से परिचित कराती है।

सम्बन्धित साहित्य का अर्थ :

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित पूर्ण सम्बन्धित कार्य की दृष्टिकोणों ज्ञानलेखों आदि से है। जिसके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपने समस्या के चयन परिकल्पनाओं के निर्माण व अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के कार्य :

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के प्रमुख पाँच कार्य है :-

1. यह अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है प्रत्येक प्रत्यय और धारणा का स्पष्ट करता है।
2. उसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समस्या क्षेत्र में अनुसंधान की स्थिति क्या है? कब क्या कहां और कैसे अनुसंधान कार्य किया है।? इसके ज्ञान द्वारा छापने अध्ययन की योजना बनाना सुविधाजनक हो जाता है।
3. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए अपनाई जाने वाली विधि प्रयोग में लाये जाने वाले योग्य उपकरण तथा आंकड़ों के विप्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाले योग्य उपकरण तथा आंकड़ों के विप्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाली प्रयुक्त विधियों को स्पष्ट करता है।
4. इस तथ्य का अभास देता है कि लिखा गया अनुसंधान कार्य किस सीमा तक सफल हुआ है या हो जायेगा और प्राप्त निष्कर्षों से उपयोगिता क्या होगी?

5. इसका यह महत्वपूर्ण कार्य समस्याओं के परिभाषित अवधारणा, बनाते समस्या के सीमांकृत और परिकल्पना के निर्माण में सहायता करना है।

पूर्व में हुये शोधों के अध्ययन के फलस्वरूप शोधकर्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि क्या अभी ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है तथा क्या अभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सका। वस्तुतः सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का अंधेरे में तीन चालाने के समान होगा। इसके अभाव में उचित दिशा में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए गुड वार स्कट्टेस कहते हैं कि एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धी अधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे। उसी प्रकार शिक्षा के लिए जिज्ञासु छात्रः अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिए उस सूचनाओं एवं खोजों से परिचित होना आवश्यक है। " इससे शोधकर्ता पहले से ही सिद्ध कर्यों को अनजाने में दोहराने से बच जायेगा तथा यह ऐसा क्षेत्र चुन सकता है जिससे लाभदायक खोज हो सकेगी तथा उसके प्रयासों से ज्ञान में सार्थक वृद्धि होगी। इससे शोधकर्ता को अनुसंधान की पृष्ठभूमि ज्ञात हो जाती है और अध्ययन की वर्तमान स्थिति से वह परिचित हो जाता है।

सम्बन्धित साहित्य की आवश्यकता :

साहित्य की समीक्षा निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है जो इस प्रकार हैं—

1. प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरों के द्वारा दिये गये अपनी समस्या से सम्बन्धित साहित्य की सूचना से भलीभांति अवगत हो।
2. शोधकर्ता सम्बन्धित साहित्य से अपनी रुचि के अनुरूप शोधकार्य का क्षेत्र चुनता है तथा इस शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विप्लेषण शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करता है।
3. शोधकर्ता साहित्य से शोध की समस्या का चयन करता है तथा साहित्य के पुर्ननिरीक्षण के अधार पर अपनी परिकल्पनायें बनाता है तथा अनुसंधान के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद—विवाद किया जा सकता है।

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से लाभ :

सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षण से अनुसंधानकर्ता की निम्नलिखित लाभ जिसका विवरण इस प्रकार है—

1. यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है।
2. यह सभी प्रकार के विज्ञानों तथा शास्त्रों में अनुसंधान कार्य का आधार है।
3. यह समस्या के चुनाव विप्लेषण एवं कथन में सहायक होता है।
4. यह शाधकर्ता के समय की बचत करता है।
5. इससे अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है।
6. शोधकर्ता को त्रुटियों से बचाता है एवं सावधान रखता है।
7. तब तक उस क्षेत्र में हो चुके कार्य की सूचना प्रदान करता है।
8. पहले किये गये कार्य के आंकड़े वर्तमान अध्ययन में सहायक होते हैं।
9. समस्या के सीमांकन में सहायक होता है।
10. अध्ययन की विधि में सुधार कर द्वारा की बचत करता है तथा शोधकर्ता में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है।

सम्बन्धित साहित्य के स्रोत :

अनुसंधानकर्ता अपने शोध से सम्बन्धित सूचनायें निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त कर सकता है इस प्रकार है :—

1. पुस्तकें।
2. बुलेटिन।
3. पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाला सामाजिक साहित्य।
4. वार्षिकी।
5. किसी विषय पर लेख।
6. शोध प्रबन्ध।
7. राजकीय प्रकाशन।
8. विश्वविद्यालय प्रकाशन।

9. अन्य प्रकाशन जैसे – राजकीय के अलावा।
10. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन
11. ज्ञान –कोष।
12. ग्रन्थ सूची तथा निर्देशिकायें।
13. शिक्षा तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी लेख सार।
14. उद्धरण के अन्य स्रोत आदि।

जिसमें वास्तविक निष्कर्ष, साथ ही किसी विशेष विषय में सैद्धांतिक और पद्धतिगत योगदान शामिल हैं। साहित्य समीक्षा द्वितीयक स्रोत हैं, और नए या मूल प्रयोगात्मक कार्य की रिपोर्ट नहीं करते हैं। अक्सर अकादमिक-उन्मुख साहित्य से जुड़े होते हैं, ऐसी समीक्षाएं अकादमिक पत्रिकाओं में पाई जाती हैं, और पुस्तक समीक्षाओं के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जो एक ही प्रकाशन में भी दिखाई दे सकते हैं। साहित्य समीक्षा लगभग हर अकादमिक क्षेत्र में शोध का आधार है। एक संकीर्ण दायरे की साहित्य समीक्षा को नए शोध प्रस्तुत करने वाले एक सहकर्मी की समीक्षा की गई पत्रिका लेख के हिस्से के रूप में शामिल किया जा सकता है, जो प्रासंगिक साहित्य के शरीर के भीतर वर्तमान अध्ययन को व्यवस्थित करने और पाठक के लिए संदर्भ प्रदान करने के लिए सेवा प्रदान करता है। ऐसे मामले में, समीक्षा आमतौर पर कार्य की कार्यप्रणाली और परिणाम अनुभागों से पहले होती है।

एक साहित्य समीक्षा का निर्माण स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र के काम का भी हिस्सा हो सकता है, जिसमें थीसिस, शोध प्रबंध या जर्नल लेख तैयार करना शामिल है। एक शोध प्रस्ताव या प्रॉस्पेक्टस में साहित्य समीक्षाएं भी आम हैं (एक दस्तावेज जो औपचारिक रूप से एक शोध प्रबंध या थीसिस शुरू करने से पहले स्वीकृत है)।

दिया गया अध्याय साहित्य की समीक्षा पर आधारित है। इस कार्य के दौरान अनेक साहित्य की समीक्षा की गई। कुछ प्रमुख समीक्षाएं दिए गए अध्याय में प्रस्तुत की गई हैं

1. रितु धनोआ (2008) ने अपने पेपर "भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन" में बताया कि हालांकि भारत के संविधान द्वारा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, लेकिन कानून और इसके अभ्यास के बीच एक बड़ा अंतर

है। . भारत में महिलाओं को हमेशा से पुरुषों से कमतर माना गया है। यद्यपि आधी आबादी महिलाओं द्वारा गठित की गई है, फिर भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है और जीवन के हर क्षेत्र में उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। वे बलात्कार, दहेज, दुल्हन जलाने, यौन उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति और तस्करी जैसे विभिन्न अपराधों के शिकार हैं।

सरकार भारत में महिलाओं की स्थिति को विकसित करने के लिए कई कदम उठा रही है और दावा कर रही है कि भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त है, लेकिन भारत में महिलाएं अतीत से पीड़ित रही हैं और आज भी विभिन्न प्रकार के अन्याय और भेदभाव का सामना करती हैं।

भेदभाव महिलाओं के जीवन का हिस्सा और हिस्सा बन जाता है। उसे जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लिंग निर्धारण परीक्षण के रूप में मां के गर्भ में प्रवेश करते ही भेदभाव का सिलसिला शुरू हो जाता है जिससे भ्रूण हत्या और कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है। कुछ स्थितियों में, उसे उसके अपने ही लोग मार रहे हैं जिनके साथ उसे दुनिया में आने पर सुरक्षित और सुरक्षित महसूस करना चाहिए। यह महिलाओं के जीवन के अधिकार के हनन को दर्शाता है। बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न और दुल्हन को जलाने, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि से अधिक उसके जीवन में हिंसा का एक रूप है।

उनके शिक्षा के अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वास्थ्य की सुरक्षा का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उनके जीवन के विभिन्न चरणों में उल्लंघन किया जाता है। आज बालिकाएं अपनी उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पा रही थीं। भारत में लगभग 60 मिलियन लड़कियां प्राथमिक शिक्षा के लाभ से वंचित हैं। विभिन्न पहलों के बावजूद लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% तक नहीं पहुंच सका। अभी भी पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को राजनीति में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। जहां तक संपत्ति का सवाल है, महिला के पास अपने नाम की संपत्ति नहीं है और न ही उसे अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिलता है जो उन्हें पैतृक संपत्ति के लाभ तक पहुंचने से वंचित करता है। विभिन्न अध्ययनों से, यह पुष्टि हो रही है कि परिवार में लड़के की तुलना में लड़की का पोषण कम होता है

जिससे लड़की की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर रूप से खराब हो जाती है। कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। कृषि में, महिलाओं का औसत वेतन पुरुषों की तुलना में औसतन 30 – 50% कम है। छेड़खानी से महिला के शरीर, स्थान और आत्मसम्मान का हनन होता है और वर्तमान समय में यह आम बात है। आज की दुनिया में आमतौर पर कोई भी जगह महिला के लिए सुरक्षित नहीं है। सड़कें, बसें, ट्रेन, सिनेमा हॉल, पार्क, समुद्र तट, यहां तक कि एक महिला का घर और पड़ोस भी ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां उसके स्वाभिमान का दुरुपयोग होता है। यह सब इंगित करता है कि कैसे महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

समग्र परिदृश्य हमारे सामने एक प्रश्न उठाता है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए ये विशेष अधिकार महिलाओं को पूर्ण स्थिति का आनंद लेने और उनके मानवाधिकारों का आनंद लेने में कैसे मदद करते हैं?

3. राधिका कुमारस्वामी (2000) संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विशेष रिपोर्टर' शीर्षक "घरेलू हिंसा का मुकाबला: राज्य के दायित्व" हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य की भूमिका और कर्तव्य पर जोर देता है। जहां तक हिंसा का संबंध है, राज्य की दोहरी भूमिका है। यह कोई मानवाधिकार उल्लंघन नहीं कर सकता है और इसे किसी भी प्रकार के मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकना और जवाब देना चाहिए। पिछले दिनों में, उल्लंघन के संदर्भ में राज्यों की भूमिका को बहुत संकीर्ण रूप से देखा जाता था, लेकिन वर्तमान संदर्भ में राज्य की भूमिका बहुत व्यापक रूप से मानी जाती है। निजी अभिनेताओं द्वारा अधिकारों का उल्लंघन होने पर आँकड़ों में निवारक और दंडात्मक उपायों का दायित्व होता है।

1992 में, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन (सीईडीएडब्ल्यू) पर समिति द्वारा सामान्य सिफारिश 19 को अपनाया गया था, जो इस बात पर जोर देती है कि यदि राज्य अधिकारों के उल्लंघन को रोकने या हिंसा के कृत्य की जांच और दंड देने के मामले में कार्य करने में विफल रहता है तो राज्य भी कर सकता है उसी के लिए जिम्मेदार माने।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा भी राज्यों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बिना किसी देरी के समाप्त करने की नीति के साथ आने का निर्देश देती है। जिसमें मौजूदा कानूनों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं को संशोधित करना या समाप्त करना शामिल है जो महिलाओं को उनके अधिकारों से भेदभाव करते हैं।

विचार के एक स्कूल का यह भी तर्क है कि घरेलू हिंसा यातना का एक रूप है और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, और अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा के खिलाफ कन्वेंशन के तहत सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

हिंसा का मुकाबला करने में राज्य की भूमिका के जवाब में कई राज्यों ने महिलाओं को हिंसा से बचाने और दुर्व्यवहार करने वाले को तुरंत दंडित करने के लिए नियम और कानून बनाए हैं। हालांकि, कानून सुधारक के सामने पत्नी बैटरी को अपराधीकरण करने की चुनौती अभी भी मौजूद है। मुख्य दुविधा यह है कि पत्नी की बैटरी को अपराध माना जाए या परामर्श और मध्यस्थता पर जोर दिया जाए।

कानूनी कार्रवाई के माध्यम से चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकारों और नागरिक समाज संगठन के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है। दृष्टिकोण एकीकृत और बहु-विषयक होना चाहिए। वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को घरेलू हिंसा के मामलों से संबंधित समझ हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा, पीड़ित महिला के वास्तविक जीवन के संदर्भ, उसकी निराशा, निर्भरता, प्रतिबंधित विकल्पों और मामले से निपटने के दौरान सशक्तिकरण की उसकी परिणामी आवश्यकता पर विचार करने की आवश्यकता है। समग्र लक्ष्य इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह अपने भविष्य के लिए स्वयं निर्णय लेने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करे।

4. मैरी एल्सबर्ग और लोरी हाइज़ (2003) "महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर शोध करना शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका" में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान के बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर हम लगभग 20 साल पहले के परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस

समय महिलाओं के खिलाफ हिंसा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान देने योग्य या चिंता का विषय नहीं माना जाता था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से समझौता करना चाहिए, और कम आत्मसम्मान विकसित करना चाहिए। यह शारीरिक अक्षमता, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग, और अवसाद सहित दीर्घकालिक जोखिम भी विकसित करता है।

इस तरह के प्रभाव के बावजूद, दुनिया भर के समाज मुद्दों के लिए चिंतित नहीं थे। समाज के इस रवैये के कारण घरेलू हिंसा पीड़िता को पूरी तरह से खामोशी का सामना करना पड़ा। विभिन्न महिला समूहों द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर वकालत की पहल की श्रृंखला द्वारा मुद्दों को सुर्खियों में लाया गया। अंत में, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को एक वैध मानवाधिकार मुद्दा माना गया।

महिलाओं की पहल के कारण आज अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लिंग आधारित हिंसा नीति निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ बोल रही हैं, जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर हिंसा के गंभीर परिणामों को पहचानती हैं। दुरुपयोग की व्यापकता और प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए अनुसंधान का अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

यद्यपि पुरुष और महिला दोनों ही पीड़ित होने के साथ-साथ हिंसा के अपराधी भी हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं को हिंसा के परिणामों का सामना करने और सहन करने का उच्च जोखिम है। बचपन में, किशोरावस्था में, या वयस्कों के रूप में उनके साथ यौन उत्पीड़न का उच्च जोखिम होता है। यदि हम महिलाओं के जीवन चक्र पर विचार करें, तो महिलाएं अपने जीवन के विभिन्न क्षणों में कई प्रकार की हिंसा की चपेट में आ जाती हैं। जन्म के पूर्व चरण में, वह लिंग चयनात्मक गर्भपात की शिकार होती है जबकि शैशवावस्था में वह कन्या भ्रूण हत्या उपेक्षा (स्वास्थ्य देखभाल, पोषण) की शिकार होती है। जब वह चाइल्डहुड स्टेज पर पहुंचती है तो वह बाल शोषण, कुपोषण और एफजीएम की शिकार हो जाती है। किशोर अवस्था में, जबरन वेश्यावृत्ति, तस्करी, जबरन कम उम्र में विवाह, मनोवैज्ञानिक शोषण, बलात्कार का खतरा होता है। प्रजनन स्तर पर, उसे ऑनर किलिंग, दहेज हत्या, अंतरंग साथी हिंसा, गैर-साथी हत्या/स्त्री हत्या, यौन तस्करी, यौन उत्पीड़न के खतरे का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान संदर्भ में हालांकि घरेलू हिंसा के प्रति चिंता बढ़ रही है लेकिन फिर भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए सार्वभौमिक रूप से सहमत शब्दावली का अभाव है। घरेलू हिंसा के पूर्वावलोकन में इस्तेमाल की जाने वाली कई शब्दावली का अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग अर्थ है। उदाहरण के लिए, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में “घरेलू हिंसा” शब्द का प्रयोग वर्तमान या पूर्व पुरुष अंतरंग भागीदारों द्वारा महिलाओं के दुरुपयोग को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। हालांकि, लैटिन अमेरिका में घरेलू हिंसा का अर्थ घर में होने वाली किसी भी हिंसा से है, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा भी शामिल है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए सार्वभौमिक सहमत शब्दावली की कमी ने लिंग आधारित हिंसा पर काम करने वाले शोधकर्ता के लिए विभिन्न चुनौतियों और खतरों को रोक दिया है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पिछली गलतियों से सीखना, “सर्वोत्तम प्रथाओं” की पहचान करना और यह पता लगाना है कि उन्हें क्या सफल बनाता है ताकि संसाधनों और प्रयासों को चैनलाइज़ किया जा सके ताकि क्षेत्र में अंतर किया जा सके।

5. सतविंदर कौर (2014) ने अपने लेख एन एनालिसिस ऑफ लैकिंग सिव्योरिटी एंड इंक्रिजिंग रेप क्राइम इन इंडिया में भारत में 2001 से 2010 तक बलात्कार की घटनाओं और बलात्कार से संबंधित विभिन्न कारकों का विश्लेषण किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे युवा महिलाओं में बलात्कार का खतरा अधिक है और इस तरह की समस्याओं को दूर करने की रणनीति पर चर्चा की।

दुनिया में महिलाओं की आबादी के बहुमत पर हावी होने के बावजूद उनकी स्थिति समाज में दयनीय है जो महिलाओं के जीवन के प्रति समाज द्वारा निर्धारित निम्न मूल्य का सूचक है। आज की दुनिया में सभी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। समाज में हो रहे सेक्स संबंधी अपराधों की एक बड़ी श्रृंखला जिनमें बलात्कार मानव अधिकारों के उल्लंघन का सबसे भयानक और गंभीर रूप है और दुनिया के कई समाजों में एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। बलात्कार की घटनाएं न केवल महिलाओं को शारीरिक चोट पहुंचाती हैं, बल्कि

महिलाओं के सबसे पोषित अधिकार, यानी उनकी गरिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा और कम से कम उनकी शुद्धता पर एक अमिट छाप छोड़ती हैं।

जहां तक यौन अपराध की बात है तो भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत ही चौंकाने वाली है। वे उन परिस्थितियों के शिकार हैं जो भारतीय समाज की संस्कृति में लैंगिक भेदभाव के बने रहने के कारण हैं। भारत में, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन अपराध मुख्य रूप से बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, छेड़खानी और यौन शोषण के लिए लड़कियों की तस्करी के रूप में ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें से बलात्कार महिलाओं को डराने और रुग्ण होने के कारण सबसे अधिक आक्रामक है। 2001 में अनाचार बलात्कार के 369 पीड़ित थे, जो 2012 में तेजी से बढ़कर 396 हो गए। यद्यपि देश में अनाचार के मामले काफी अधिक हैं, लेकिन इससे जुड़े सामाजिक अपमान के कारण अदालतों में अनाचार के बहुत कम मामले दर्ज किए गए हैं और यहां तक कि रिपोर्ट किए गए मामलों में भी अदालतों ने समस्या के बारे में प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं लिया है।

ऐसे अपराधों से बचपन भी सुरक्षित नहीं है। 2007 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक अध्ययन से पता चला कि भारत के 13 राज्यों में 12,447 बच्चों में से 20.9 प्रतिशत बच्चों ने यौन शोषण के गंभीर रूपों का सामना किया था। परिणाम दर्शाते हैं कि बच्चों पर बलात्कार की घटनाएं 2001 में 2113 से बढ़कर 2012 में 8541 हो गई हैं। जहां तक आयु कारक का संबंध है, बलात्कार पीड़ितों का सबसे सहनशील और सबसे गंभीर वर्ग 19 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई विशेष कानूनों का अस्तित्व, भारत में बलात्कार के मामलों में वृद्धि जारी है। बलात्कार की वास्तविक संख्या दर्ज होने से बहुत दूर है, क्योंकि रिपोर्ट न की गई संख्या बहुत अधिक है।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब हमारे नीति निर्माताओं, परिवार व्यवस्था, समुदाय और स्वयं महिलाओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है यदि वे वास्तव में खुद को वास्तव में स्वतंत्र, मजबूत और सुरक्षित देखना चाहते हैं। बलात्कार पीड़ितों के लिए घर, समाज, कार्यस्थलों और कॉलेजों में एक परिष्कृत वातावरण, गैर-भेदभावपूर्ण उपचार और मजबूत सामाजिक समर्थन की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सीवरेज और शौचालय की सुविधा, पानी की आपूर्ति आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च

प्राथमिकता दी जानी चाहिए। . समाज में महिलाओं पर होने वाले ऐसे अपराधों को मिटाने के लिए वर्तमान परिदृश्य में पुरुषों के प्रयास और भागीदारी एक आवश्यक घटक है। प्रत्येक पुरुष को स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से पुरुषों की हिंसा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और महिलाओं के खिलाफ इस भयावह क्रूरता को समाप्त करने के लिए अन्य पुरुषों को चुनौती देनी चाहिए।

6. मुबिका ऑगस्टीन कुदकवाश, बुकालिया रिचर्ड (2015) ने अपने प्रकाशन में सशस्त्र संघर्ष और महिलाओं पर उनके प्रभाव के 40 मामलों का विश्लेषण किया जो महिलाओं पर सशस्त्र संघर्षों के प्रभावों को स्थापित करने के लिए दुनिया भर में सशस्त्र संघर्षों पर आधारित थे।

दुनिया भर में कई युद्ध लड़े गए हैं और इस तरह के सशस्त्र संघर्षों की मुख्य शिकार महिला इंसान रही हैं। दुनिया भर में सशस्त्र संघर्षों की घटनाओं को अच्छी तरह से प्रचारित किया गया है, लेकिन इस तरह के संघर्षों के प्रभावों को उन मुद्दों को उजागर करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं किया गया है, जिन्होंने महिलाओं और लड़कियों को किसी न किसी तरह से पीड़ित किया है।

सशस्त्र संघर्ष के कारणों को अक्सर तेल, धातु, हीरे, ड्रग्स या विवादित क्षेत्रीय सीमाओं जैसे आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित करने के प्रयासों से जोड़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, शक्ति और संसाधनों के वितरण में असमानता अधिक स्पष्ट हो गई है। राष्ट्र-राज्यों के बीच और भीतर संरचनात्मक असमानताओं के साथ, इस असमानता ने अधिक क्षेत्रीय संघर्षों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों को बढ़ा दिया है। हालांकि, सभी स्तरों पर संघर्ष के प्रभाव ने महिलाओं को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। सशस्त्र का सबसे प्रचलित प्रभाव: संघर्ष बलात्कार की शिकार महिलाओं का आघात और कलंक थे; महिलाओं और महिलाओं के विस्थापन को विधवापन में डाला जा रहा है।

एक अध्ययन के अनुसार, प्रत्येक 100 में से 43 महिलाएं आंतरिक संघर्ष क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की हिंसा का शिकार हुई हैं। युद्ध संघर्षों का प्रभाव विस्थापन, विधवा, यौन शोषण, अन्य दुर्व्यवहार और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव हैं। इस्तेमाल की जाने वाली हिंसा के रूप – बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन दासता, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन नसबंदी और

गर्भधारण की जबरन समाप्ति। महिलाओं का बलात्कार हमलावर के लिए पराजित पुरुषों को प्रतीकात्मक और शारीरिक रूप से अपमानित करने का एक साधन है।

कुछ संदर्भों में, संघर्ष के अभिनेता यौन हिंसा को दंड के रूप में और नियंत्रण में समुदाय के भीतर महिला आबादी के लिए एक सामान्य चेतावनी के रूप में उपयोग करते हैं (एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2004)। तथ्य यह है कि आम तौर पर, महिलाएं लड़ने के लिए नहीं जाती हैं और बड़े पैमाने पर निहत्थे और असुरक्षित रहती हैं, जब नैतिक, सामुदायिक और संस्थागत सुरक्षा के पारंपरिक रूप विघटित हो गए हैं, और हथियारों का प्रसार हुआ है, जिससे महिलाएं युद्ध के दौरान विशेष रूप से कमजोर हो जाती हैं। जलाऊ लकड़ी या पानी का संग्रह अक्सर युवा लड़कियों और महिलाओं को खतरों के खतरे में डालता है, जिसमें अपहरण, यौन शोषण और बारूदी सुरंगों के संपर्क में आना शामिल है। सामाजिक दृष्टिकोण भी महिलाओं और लड़कियों की भेद्यता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, परिवारों ने अक्सर गलत तरीके से यह मान लिया है कि एक बुजुर्ग महिला या बच्चों वाली महिला नुकसान से सुरक्षित रहेगी और उन्हें संपत्ति की रक्षा के लिए छोड़ दिया है जबकि परिवार के बाकी लोग भाग जाते हैं।

भले ही महिलाएं सशस्त्र संघर्षों के दौरान सीधे तौर पर घायल न हों, उनके परिवारों द्वारा झेली गई तबाही और हिंसा का खतरा महिलाओं के अलगाव में योगदान कर सकता है। विधवापन, शहरों की ओर पलायन और हिंसा से बचने के लिए घर के अंदर रहना, ये सभी सामाजिक संस्थाओं को तोड़ने और महिलाओं को अलग-थलग करने का काम करते हैं। इसके अलावा, विधवा महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद भूमि के स्वामित्व का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (एलओएम) का अनुमान है कि 2001 में, 700,000 से 2 मिलियन महिलाओं और बच्चों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार तस्करी की गई थी। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि इस गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सशस्त्र संघर्ष से जुड़ा है।

7. वी.के.मदान, आर.के. सिन्हा (2013) पेपर द डायनामिक्स ऑफ रेप इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में चर्चा की गई कि हाल के वर्षों में अपराध कैसे फला-फूला और राष्ट्रीय समस्या बन गया। यह पेपर भारत के संबंध में बलात्कार की गतिशीलता को संबोधित करता है।

प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों में बलात्कार होते रहे हैं। इसे भी अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है और गलत तरीके से पेश किया जाता है। बलात्कार एक जटिल घटना है जिसके कई आयाम हैं। यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है, और समकालीन सोच के लिए एक चुनौती है। शायद बलात्कार पूरी संस्कृति में सबसे अधिक रिपोर्ट न किया गया अपराध है। अपराधी को दंडित करने के लिए मजबूत कानून, जांच में अभ्यास और प्रक्रिया, मीडिया में हाई प्रोफाइल कवरेज और पीड़ितों को उपलब्ध समर्थन के बावजूद बलात्कार के अपराध में जबरदस्त वृद्धि हुई है। हालांकि अपराधियों की केवल एक छोटी संख्या को न्याय के लिए लाया जाता है, और पीड़ितों को नियमित रूप से अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। अधिकांश अन्य अपराधों से निपटने की तुलना में बलात्कार से निपटना कहीं अधिक जटिल है।

आधुनिक भारत में महिलाएं अधिकांश क्षेत्रों में नेतृत्व का स्थान रखती हैं। प्राचीन भारत में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर या उससे भी बेहतर दर्जा प्राप्त था। नारी शक्ति का दिव्य अवतार शक्ति के रूप में जाना जाता था और है। भारत में, माता वैष्णो देवी मंदिर जैसे शक्ति को समर्पित कई मंदिर हैं जहाँ वार्षिक तीर्थयात्रियों की संख्या दस मिलियन से अधिक है। हालाँकि, बलात्कार एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में मौजूद है। बलात्कार के कारणों में यौन सुख, सामाजिक आर्थिक, शक्ति, परपीड़न, क्रोध और विकासवादी शामिल हैं।

बलात्कार की धारणा और समझ व्यापक रूप से भिन्न होती है। उदारवादी धारणा बलात्कार को अन्य हमलों की तरह एक हमले के रूप में देखती है जबकि कट्टरपंथी धारणा मर्दानगी के कारण प्रमुख भूमिका को ध्यान में रखती है।

पीड़ितों पर बलात्कार का प्रभाव गंभीर हो सकता है। एक पीड़ित गंभीर रूप से आहत हो सकता है, विभिन्न तनाव विकारों से पीड़ित हो सकता है, और सामाजिक कलंक का सामना कर सकता है।

बलात्कार के अपराध को संबोधित करने के लिए देश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) मौजूद है। यह अपराध और सजा के सभी मामलों की एक विस्तृत सूची का वर्णन करता है। पहला प्ले दस्तावेज़ 1860 में 511 धाराओं के साथ तैयार किया गया था, और 1862 में लागू हुआ। तब से स्थिति और गंभीरता को देखते हुए प्ले में कई संशोधन किए गए हैं। दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद, भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने आपराधिक कानूनों में संशोधन और यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्ती से निपटने के लिए दंड का सुझाव दिया और समिति की सिफारिशों के आधार पर एक आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित किया गया। बलात्कार शब्द को यौन हमले से बदल दिया गया है और इसमें प्रवेश के बिना हमला शामिल है, और लिंग में प्रवेश के अलावा किसी भी हद तक प्रवेश भी एक अपराध है। एसिड अटैक, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ताक-झांक, पीछा करने जैसी सजा के साथ नए अपराध जोड़े गए हैं।

इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि कानून आवश्यक हैं लेकिन बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह वांछनीय है कि बलात्कार की चुनौती को कानून और प्रवर्तन के अलावा बहु-विषयक दृष्टिकोण से नए सिरे से देखा जाना चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक पहलुओं सहित डेटा, विश्लेषण और विचारों का संलयन, और विषयों से उपकरणों के विलय को प्रोत्साहित करना, जटिल सामाजिक समस्या का समाधान खोजने के लिए एक व्यावहारिक और ठोस दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए।

8. बर्कले हास स्कूल ऑफ बिजनेस और बर्कले हास स्कूल ऑफ लॉ (2015) ने संघर्ष और सामाजिक उथल-पुथल में यौन हिंसा के लिए एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमन इंडिया की प्रतिक्रिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में यौन हिंसा की शिकार महिलाओं और उनके सहयोगियों के न्याय तक पहुंचने के प्रयासों का विश्लेषण किया है। इन संदर्भों में और

प्रतीकात्मक तरीकों की पहचान करने के लिए भारतीय कानूनी प्रणाली प्रभावी निवारण प्रदान करने में सफल रही या विफल रही।

भारत में महिलाएं लगातार हिंसा का अनुभव करती हैं। . . गर्भ से कब्र तक। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग हर बीस मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। सशस्त्र संघर्ष और सामूहिक हिंसा के दौरान महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से यौन हिंसा की चपेट में आ जाती हैं। वास्तव में, लिंग आधारित अपराध सशस्त्र संघर्ष और सामूहिक हिंसा की एक सामान्य विशेषता है जिसने स्वतंत्रता के बाद से भारत को प्रभावित किया है।

9. नरगिस यस्मीन (2015) ने अपने लेख एसिड अटैक इन द बैक ड्रॉप ऑफ इंडिया एंड क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, 2013 में इस जघन्य अपराध के कारणों और इसके परिणामों पर चर्चा की। उन्होंने भारत के बैकड्रॉप में विभिन्न देशों में एसिड अटैक के कानूनों की तुलना करने की भी कोशिश की।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं पर वर्चस्व और भेदभाव किया गया है और महिलाओं की पूर्ण उन्नति को रोका गया है। एसिड अटैक, जिसे औपचारिक रूप से विट्रियल उम्र के रूप में जाना जाता है, अंतरंग आतंकवाद का एक कार्य है जिसमें डिफिगरेशन के मुख्य इरादे से सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दूसरे पर फेंकना शामिल है। इन अम्लों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं। यह दुखद, क्रूर और जघन्य अपराध आजकल बढ़ता ही जा रहा है और मासूम लड़कियां/महिलाएं तेजाब हमले का शिकार हो रही हैं। एसिड अटैक हिंसा कई देशों में होती है, लेकिन यह मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया और पाकिस्तान में प्रचलित है। एसिड अटैक के रिपोर्ट किए गए मामले महिलाओं पर, विशेष रूप से युवा महिलाओं/लड़कियों पर उनके सूटर्स के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के लिए, शादी के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के लिए, दहेज से इनकार करने / विवाद, घरेलू झगड़े, संपत्ति पर विवाद आदि के लिए किए जाते हैं। कारण इसके पीछे यह है कि, हमलावर अपनी अस्वीकृति, सम्मान और शर्म की हानि,

असुरक्षा, ईर्ष्या, पितृसत्ता, आक्रामकता और हताशा को सहन नहीं कर सकता है; इस सब के बीच उसका तथाकथित पुरुष अहंकार आ जाता है, और इस प्रकार वह शरीर को नष्ट करके बदला लेता है, विशेष रूप से उन महिलाओं के चेहरे को, जिन्होंने उसे मना करने का साहस किया। यह पीड़ित को झुलसा हुआ, अंधा और क्षत-विक्षत छोड़ देता है, यह मानव मांस और यहां तक कि हड्डियों को भी पिघला देता है, जिससे कष्टदायी दर्द और आतंक होता है और उनके शेष जीवन के लिए जख्मी हो जाते हैं।

10. यूरोपीय आयोग (2010) ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा नामक रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की प्रकृति और परिणामों पर प्रकाश डाला। यूरोपीय संघ 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा' को परिभाषित करता है, "लिंग-आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होती है, जिसमें इस तरह के कृत्यों की धमकी, जबरदस्ती या मनमाने ढंग से वंचित होना शामिल है। स्वतंत्रता की, चाहे सार्वजनिक या निजी जीवन में हो। हालांकि सार्वजनिक जागरूकता में सुधार और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को और अधिक जगह देने के मामले में यूरोपीय संघ में निस्संदेह कुछ प्रगति हुई है, सभी सदस्य राज्यों में महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है अपमानजनक भागीदारों के हाथ। यूरोप की परिषद के अनुसार, चार में से एक यूरोपीय महिला अपने जीवन में किसी समय घरेलू हिंसा का अनुभव करती है, और प्रत्येक वर्ष 6-10% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। पांच संभावित प्रकार की हिंसा में से विचाराधीन, यौन और शारीरिक हिंसा पूरे यूरोपीय संघ में सबसे गंभीर है, जिसमें 85% उत्तरदाताओं ने हिंसा के इन रूपों को बहुत गंभीर माना है। 71% मनोवैज्ञानिक हिंसा को पाते हैं बहुत गंभीर हों, जबकि 69% प्रतिबंधित स्वतंत्रता के बारे में ऐसा ही कहते हैं और 64% हिंसा के खतरों के बारे में ऐसा ही कहते हैं। यूरोपीय संघ में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का तीसरा और चौथा सबसे आम कारण गरीबी या सामाजिक बहिष्कार (77%) और बेरोजगारी (75%) है।

यूरोपीय संघ में लोगों के रवैये से पता चलता है कि यूरोपीय संघ के उत्तरदाताओं के भारी बहुमत (84%) का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा अस्वीकार्य है और हमेशा कानून द्वारा दंडनीय होना चाहिए। एक ध्यान देने योग्य अल्पसंख्यक (12%) का मानना है

कि इस तरह की हिंसा अस्वीकार्य है लेकिन हमेशा कानून द्वारा दंडनीय नहीं होनी चाहिए, जबकि एक बहुत छोटा फ्रिंज सोचता है कि घरेलू हिंसा कुछ परिस्थितियों (2%) या सभी परिस्थितियों (1%) में स्वीकार्य है। . यह यूरोपीय संघ में लोगों की राय और मानसिकता के स्तर को दर्शाता है।

अधिकांश यूरोपीय संघ के नागरिकों का मानना है कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कानून हैं, हालांकि अल्पसंख्यक कानूनी स्थिति को नहीं जानने की बात स्वीकार करते हैं। हालांकि, सात सदस्य राज्यों में, अधिकांश लोगों को लगता है कि उनके देश में रोकथाम से संबंधित कोई कानून नहीं हैं या कानूनों से अनजान हैं।

इस रिपोर्ट की सबसे उत्साहजनक खोज यह है कि सामान्य तौर पर, पिछले सर्वेक्षण के समय से एक दशक पहले 15 देशों के बीच स्पष्ट प्रगति हुई है। इस मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ी है, घरेलू हिंसा के प्रति सहनशीलता कम हुई है और अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का समर्थन बढ़ा है। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि अधिक से अधिक लोग मीडिया में घरेलू हिंसा के बारे में सुनते हैं जो इस बात का संकेत हो सकता है कि यह मुद्दा अब 'वर्जित' से कम हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय आयोग द्वारा शुरू की गई बहस का घरेलू हिंसा के प्रति लोगों की जागरूकता पर प्रभाव पड़ा है। हम सर्वेक्षण के परिणामों से यह भी मान सकते हैं कि सूचना अभियानों जैसी पहलों ने इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया है। हालांकि, यह इस तथ्य को छुपाता नहीं है कि समस्या यूरोपीय समाज में व्याप्त है, बड़ी संख्या में लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से उन महिलाओं को जानते हैं जो हिंसा से पीड़ित हैं, और वे ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो ऐसी हिंसा कर रहे हैं।

तृतीय – अध्याय

अनुसंधान क्रियाविधि

अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के 'Research' शब्द का हिन्दी रूपान्तर है जिसे दो भागों 'Re' 'Search' में विभाजित किया जा सकता है। पहले अर्थात् 'Re' शब्द का अर्थ है पुन तथा जबकि दूसरे अर्थात् 'Search' शब्द का अर्थ है खोज करना।

अतः अनुसन्धान का शब्दिक अर्थ पुनः खोज करना है। दि न्यू सेन्चूरी डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में विशेष रूप से सावधानी के साथ खोज करना, तथ्यों अथवा सिद्धान्तों का अन्वेषण करने के लिए विषय –सामग्री की निरन्तर सावधानीपूर्वक पूछताछ अथवा जाँच पड़ताल करना है।

सी० वी० गुड के अनुसार, आदर्श रूप में अनुसंधान किसी समस्या के बारे में सावधानी एवं निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेषण है जिसमें गंथ सम्भव प्रमाणित तथ्यों में अन्तर निर्वचन तथा सामान्य रूप से सामान्यीकरण को आधार बनाया जाता है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों के अनुसार अनुसन्धान वस्तुओं अवधारणाओं या प्रतीकों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है। जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा ज्ञान का विकास, प्रामाणिकता की जाँच अथवा सत्यापन की जाँच होता है चाहे ज्ञान व्यवहार से सहायक हो या कला में।

इस प्रकार अनुसंधान का अर्थ केवल खोज करना ही नहीं है अपितु किसी प्रघटना या समस्या के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना या उपलब्ध ज्ञान में किसी प्रकार का सषोधन करना भी है। शोध शब्द का प्रयोग से शुद्धि, संस्कार या सषोधन के अर्थ के रूप में किया जाता है। सामान्यतः नवीन की दिशा में किया गया कमबद्ध प्रयास ही अनुसन्धान कहलाता है।

अनुसन्धान प्ररचना का अर्थ एवं परिभाषाएँ

अनुसन्धान प्ररचना शब्द का अर्थ समझाने के लिए पहले अनुसन्धान तथा प्ररचना शब्दों का अर्थ समझ लेना जरूरी है।

प्ररचना का अर्थ योजना बनाना है अर्थात् प्ररचना पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है ताकि परिस्थिति पैदा होगे पर इसका प्रयोग किया जा सके। यह सूझ-बूझ एवं पूर्वानुमान की प्रक्रिया है जिसका है उद्देश्य अपेक्षित पर नियन्त्रण रखना है। “अनुसंधान प्ररचना आकड़ों के संकलन तथा विप्लेषण की दषाओं की उस व्यवस्था को कहते है जिसका लक्ष्य अनुसंधान के उद्देश्य की प्रासंगिकता तथा कार्यविधि की मितव्ययिता का समन्वय करना है।

अध्ययन की कार्य प्रणाली

हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन में अनुसंधान का विशेष महत्व है। समाज और राष्ट्र की प्रगति का शोध के परिणामों द्वारा पहचाना जाता है क्योंकि समाज व राष्ट्र की मूल समस्याओं का समाधान शोध कार्यो द्वारा किया जाता है। शोध कार्यो द्वारा ज्ञान वृद्धि के साथ मानव विकास तथा कल्याण का महत्व दिया जाता है।

अनुसंधान की अर्थ व परिभाषा

अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित तथा नियत्रित अध्ययन है जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित चारों व घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धो का अन्वेषण तथा विप्लेषण उपयुक्त सांख्यिकीय विधि तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है।

परिभाषा

जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार

अनुसंधान अधिक औपचरिक व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिससे वैज्ञानिक विधि विप्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है।

जार्ज0 जे0 मुल के अनुसार

शैक्षिक समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक बिधि के प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान करते है।

कार्यप्रणाली अध्ययन के क्षेत्र में लागू विधियों का व्यवस्थित, सैद्धांतिक विश्लेषण है। इसमें ज्ञान की एक शाखा से जुड़े तरीकों और सिद्धांतों के शरीर का सैद्धांतिक विश्लेषण शामिल है। आमतौर पर, इसमें प्रतिमान, सैद्धांतिक मॉडल, चरण और मात्रात्मक या गुणात्मक तकनीक जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। वर्तमान अध्ययन भी व्यवस्थित जांच की मदद से किया गया है और वैज्ञानिक पद्धति को भी लागू किया

गया है। प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने के लिए विभिन्न विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में इस शोध परियोजना में प्रयुक्त विधियों एवं उपकरणों का वर्णन किया गया है।

दुनिया भर में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों, सभी जातियों, धर्मों और राष्ट्रियताओं की महिलाओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अनुभव किया जाता है। यह पुरुषों¹ द्वारा अत्यधिक अपराध किया जाता है। यह आज दुनिया में मानवाधिकारों का सबसे व्यापक उल्लंघन है। इसके रूप सूक्ष्म और स्पष्ट दोनों हैं और विकास पर इसका प्रभाव गहरा है। और यह दुनिया भर की संस्कृतियों में इतनी गहराई से अंतर्निहित है कि यह लगभग अदृश्य है।

हिंसा शब्द लैटिन शब्द विज़ से निकला है, जिसका अर्थ है बल और दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक श्रेष्ठता का उपयोग करने और बाधा की धारणाओं को संदर्भित करता है। हिंसा उत्परिवर्ती है, क्योंकि यह बहुत अलग समय, स्थानों, परिस्थितियों और वास्तविकताओं से प्रभावित होती है। हिंसा को सहन किया जाता है और निंदा की जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर हिंसा मौजूद है, अगर मानव जाति, अलग, तेजी से जटिल और एक ही समय में अधिक खंडित और स्पष्ट रूप धारण करती है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा लिंग आधारित हिंसा को परिभाषित करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को इस प्रकार समझा जाना चाहिए: "लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ित होने की संभावना है, जिसमें ऐसी धमकी भी शामिल है। कार्य, जबरदस्ती या मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करना, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में हो"।

परिभाषा को घोषणा के अनुच्छेद 2 में बढ़ाया गया है, जो तीन क्षेत्रों की पहचान करता है जिनमें केवल हिंसा होती है:

1. परिवार में होने वाली शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा, जिसमें मारपीट भी शामिल है; घर में महिला बच्चों का यौन शोषण; दहेज से संबंधित हिंसा; वैवाहिक बलात्कार; महिला जननांग विकृति और महिलाओं के लिए हानिकारक अन्य पारंपरिक प्रथाएं; गैर-जीवनसाथी हिंसा; और शोषण से संबंधित हिंसा;

2. शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा जो सामान्य समुदाय के भीतर होती है, जिसमें बलात्कार भी शामिल है; यौन शोषण; काम पर, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जगहों पर यौन उत्पीड़न और धमकी; महिलाओं की तस्करी; और जबरन वेश्यावृत्ति;
3. शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा, जहां कहीं भी होती है, राज्य द्वारा की जाती है या उसे माफ कर दिया जाता है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं पर वर्चस्व और भेदभाव किया गया है और महिलाओं की पूर्ण उन्नति को रोका गया है।”

सभी समाजों में, गरीबी, भेदभाव, अज्ञानता और सामाजिक अशांति महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सामान्य भविष्यवक्ता हैं। फिर भी एक महिला की गरिमा और सुरक्षा के सबसे स्थायी दुश्मन पुरुष प्रभुत्व और महिला अधीनता को बनाए रखने के उद्देश्य से सांस्कृतिक ताकतें हैं—अक्सर आदरणीय परंपरा के नाम पर बचाव किया जाता है। पूरे जीवन चक्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक पैटर्न, कुछ पारंपरिक या प्रथागत प्रथाओं के हानिकारक प्रभावों और जाति, लिंग, भाषा या धर्म से जुड़े चरमपंथ के सभी कृत्यों से उत्पन्न होती है जो परिवार में महिलाओं को निम्न स्थिति को कायम रखती हैं, कार्यस्थल, समुदाय और समाज।

विकासशील देशों में, महिलाओं के खिलाफ हिंसक प्रथाओं को अक्सर सांस्कृतिक बुनाई की किस्में के रूप में मान्यता दी जाती है और उनका बचाव किया जाता है। उदाहरण के लिए, पत्नी की पिटाई को कई देशों में प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है – गीतों, कहावतों और शादी समारोहों में मनाया जाने वाला एक मर्दाना विशेषाधिकार। पति का अपनी पत्नी को पीटने या शारीरिक रूप से डराने का अधिकार कई समाजों में एक गहरी मान्यता है। . यहां तक कि महिलाएं भी अक्सर कुछ शर्तों के तहत एक निश्चित मात्रा में शारीरिक शोषण को उचित मानती हैं। हिंसा का औचित्य लैंगिक मानदंडों से उपजा है – रिश्तों में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में विकृत विचार।

उत्पीड़न, मारपीट और यौन हमले के खतरे से मुक्ति एक ऐसी अवधारणा है जिसके बारे में ज्यादातर महिलाओं को कल्पना करना मुश्किल होता है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाज के ताने-बाने में इस हद तक बुना जाता है कि पीड़ित कई महिलाओं को लगता है कि उनकी गलती है। . हिंसा को अंजाम देने वालों में से कई मजबूत सामाजिक संदेशों द्वारा उचित महसूस करते हैं जो कहते हैं कि बलात्कार, पिटाई, यौन उत्पीड़न, बाल शोषण और हिंसा के अन्य रूप स्वीकार्य हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की मीडिया में छवियां, जो बलात्कार या यौन दासता के साथ-साथ महिलाओं और लड़कियों के यौन वस्तुओं के रूप में उपयोग को दर्शाती हैं, जिसमें पोर्नोग्राफी भी शामिल है, ऐसी हिंसा के निरंतर प्रसार में योगदान देने वाले कारक हैं, जो बड़े पैमाने पर समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, बच्चे और युवा।

प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों में बलात्कार होते रहे हैं। इसे भी अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है और गलत तरीके से पेश किया जाता है। बलात्कार एक जटिल घटना है जिसके कई आयाम हैं। यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है, और समकालीन सोच के लिए एक चुनौती है। शायद बलात्कार पूरी संस्कृति में सबसे अधिक रिपोर्ट न किया गया अपराध है। अपराधी को दंडित करने के लिए मजबूत कानून, जांच में अभ्यास और प्रक्रिया, मीडिया में हाई प्रोफाइल कवरेज और पीड़ितों को उपलब्ध समर्थन के बावजूद बलात्कार के अपराध में जबरदस्त वृद्धि हुई है। हालांकि अपराधियों की केवल एक छोटी संख्या को न्याय के लिए लाया जाता है, और पीड़ितों को नियमित रूप से अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। अधिकांश अन्य अपराधों से निपटने की तुलना में बलात्कार से निपटना कहीं अधिक जटिल है।

अनुसंधान क्रियाविधि

यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों के स्रोतों पर आधारित है। डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), नई दिल्ली, प्दकपेंजंज.बवउ, भारत की जनगणना और भारत के चुनाव आयोग की आधिकारिक रिपोर्टों से एकत्र किया जाता है। एनसीआरबी डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत

दर्ज अपराधों पर आधारित है। इसके अलावा, इस अध्ययन ने घरेलू हिंसा को समझने के लिए ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और सैद्धांतिक तरीकों को लागू किया है।

अध्ययन का उद्देश्य:

- प्राचीन काल से आधुनिक काल की महिलाओं की स्थिति का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अर्थ, प्रवृत्ति और प्रकार का अध्ययन करना।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का सैद्धांतिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।
- घरेलू हिंसा संबंधित कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करना।
- महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने संबंधी सुझाव देना।
- घरेलू हिंसा को रोकने संबंधी सुझावों को प्रस्तुत करना।

अध्ययन की रूपरेखा:

प्रस्तुत लघु शोध 6 अध्यायों में विभाजित है

1. परिचय
2. साहित्य की समीक्षा
3. अनुसंधान क्रियाविधि
4. भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की स्थिति
5. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
6. निष्कर्ष और सुझाव

महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया भर में एक समस्या है। यह सभी जातियों, जातीय समूहों, वर्गों और राष्ट्रियताओं की महिलाओं को प्रभावित करता है। यह व्यक्तिगत महिलाओं के लिए एक जीवन-धमकी समस्या है और समाजों के लिए एक गंभीर समस्या है। हिंसा

दुनिया भर में सभी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक वर्गों में लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक बाधाओं को तोड़ता है, महिलाओं के समाज में पूरी तरह से भाग लेने के अधिकार को बाधित करता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा घरेलू शोषण से लेकर बलात्कार, बाल विवाह और महिला खतना तक, कई तरह के निराशाजनक रूप लेती है। ये सभी सबसे मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं।

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की समस्या कोई नई नहीं है। यदि सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित अभिलेख उपलब्ध हैं, तो भारतीय समाज में महिलाएं दुर्व्यवहार, अपमान, यातना और शोषण की शिकार रही हैं। ये रिकॉर्ड महिलाओं के अपहरण, बलात्कार, हत्या और प्रताड़ना की घटनाओं के साथ दोहराए जाते हैं। फिर भी, अफसोस की बात है कि हिंसा की शिकार महिलाओं को सामाजिक समस्याओं पर साहित्य या आपराधिक हिंसा पर साहित्य में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। न ही यह समझाने का कोई प्रयास किया गया है कि जनता और शिक्षाविदों दोनों ने इतने लंबे समय तक इस तथ्य की अनदेखी क्यों की है कि हमारे समाज में महिलाओं का लगातार बेरहमी से शोषण किया जाता रहा है।

पीड़ितों और उनके परिवारों को होने वाले कष्टों के संदर्भ में, यह शायद सबसे कठोर सजा है, जो उन्हें दी जा सकती है। पीड़ित महिला को उसके खिलाफ किए गए एक ही राक्षसी द्वारा जीवन भर के लिए प्रेतवाधित किया जाता है और यह उसे लगभग हर कदम पर शर्मिंदगी में डाल देता है; दोस्तों के बीच हो, शादी में हो, अगर संभव हो तो, या किसी भी आकार में उसका शेष जीवन हो। सभी उद्देश्यों के लिए, वह एक बहिष्कृत हो जाती है। यह उसके भविष्य के अस्तित्व में भारी बदलाव का प्रतीक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अपराध की अधिकांश पीड़ित आत्महत्या कर लेती हैं। इस अपराध का सबसे बुरा पहलू यह है कि संबंधित महिला को किसी भी तरह जिम्मेदार हुए बिना उस पर जो कुछ भी थोपा गया है, उसके लिए भुगतना पड़ता है। यह न केवल पीड़िता के शरीर का शारीरिक उल्लंघन है, बल्कि उसकी मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संवेदनाओं पर भी आक्रमण है। यह उसके गर्व की भावना, सुरक्षा की भावना, पवित्रता की भावना, और भविष्य की आशाओं, आकांक्षाओं और सुखी वैवाहिक जीवन के सपनों के लिए भूकंप जैसे झटके का विनाश है।

जहां तक भारतीय परिदृश्य का संबंध है, पिछले कुछ दशकों में, घटना के संबंध में बढ़ते सबूतों के साथ, महिलाओं के खिलाफ अपराध ने कई संबंधित नारीवादियों, मानवाधिकार समूहों, सामाजिक वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्य करने वालों का ध्यान आकर्षित किया है।

भारत जैसे बड़े और जटिल देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आयाम और समस्याएं आसान समाधान नहीं देती हैं। मानक निर्धारित करना पहला कदम है, और जबकि यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक है, यह पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन होना चाहिए। कानून के शासन और अधिकारों और अधिकारों के उल्लंघन के लिए कानूनी उपायों का सहारा लेना चाहिए।

भारतीय संविधान, जो देश का मौलिक कानून है, में महिलाओं के लाभ और सुरक्षा के लिए कई प्रावधान हैं। समानता और गैर-भेदभाव की अवधारणा को भारतीय संविधान में अपना उचित स्थान मिलता है। इसके अलावा, यह राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने में भी सक्षम बनाता है। मौलिक अधिकारों के अलावा, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधानों को भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। हालाँकि, संवैधानिक संरक्षण और कई विधानों के बावजूद, लैंगिक भेदभाव और अन्याय होते रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो लोग कानूनों को लागू करते हैं या उनकी व्याख्या करते हैं वे हमेशा लैंगिक न्याय अवधारणा के दर्शन को पूरी तरह से साझा नहीं करते हैं।

भारतीय महिलाएं, न्याय तक पहुंच के लिए आवश्यक सभी पूर्वापेक्षाओं के संबंध में, कुल मिलाकर विकलांग हैं। व्यापक निरक्षरता, सांस्कृतिक बाधाओं और अधीनता से वे पीड़ित हैं, और कानून की अमित्र प्रक्रिया ने ज्यादातर महिलाओं को कानून और अदालतों से दूर रखा है, जिन्हें समस्याएं हैं। पीड़ित महिलाओं को राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ विभिन्न अनुभव हैं। वे हमेशा सुरक्षा के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली पर निर्भर नहीं रह सकते। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के मामले में, हिंसा को अपराध घोषित करने वाले कानूनों में अक्सर अंतराल और अस्पष्टताएं मौजूद होती हैं। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा से व्यापक रूप से निपटने के बजाय कानून अलग-अलग होते हैं, हिंसा के विशिष्ट रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब कानून लागू

होता है, तो अक्सर कमजोर कानून प्रवर्तन होता है। यह पीड़ित की उदासीनता और अविश्वास और व्यवस्था से बचने की ओर ले जाता है। कुछ स्थितियों में, जैसे कि क्रूरता और दहेज हत्या, पुलिस और अन्य प्रवर्तन अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा के रूप में काम करता है।

अध्याय—चतुर्थ

भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की स्थिति

आज कल शायद ही कोई विषय सामाजिक विज्ञानों में शाधकर्ताओं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, योजना, दलों और सुधारकों का ध्यान इतना आकृष्ट करता हो, जितना कि महिलाओं की समस्याओं के अध्ययन के उपागम जरा-विज्ञान वृद्ध होने की प्रक्रियाओं का अध्ययन के अध्ययन से लेकर मनोरोग विज्ञान और अपराध विज्ञान तक होते हैं। परन्तु महिलाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है औ जिससे बचा गया है। वह है महिलाओं के विरुद्ध की समस्या।

महिलाओं का उत्पीड़न—

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानित यातना और शोषण का शिकार रही हैं। जितने काल के हमारे पास सामाजिक परिवर्तन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है, दनके आधार पर यह कहा जा सकता है आज शनैःशनैः महिलाओ को पुरुषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोग माना जाने लगा है परन्तु कुछ दशक पहले तक दनकी स्थिति दयनीय थी। विचधाराओं, संस्तागत रिवाजों, और समाज पें प्रचलित प्रतिमानों ने दनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है इनमे से कुछ व्यावहारिक रिवाज आज भी पनप रहे हैं। स्वाधीनता के प्छात हमारे समाज में महिलाओं के सर्मथन मे बनाये गये कानूनो, महिलाओं मे शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वातन्त्रता के बावजूद असंख्य

महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार हैं उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण कया जाता है उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है या उनको अत्मा हत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉड ब्यूरो (NCRB) के द्वारा जारी नवीन आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रभर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 2010 के बाद से 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज है (टाइम्स ऑफ इंडिया, 27 अगस्त 2013)

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, कि महिलाओं के प्रति अपराध की विचारधारा की कोई सरल

या सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, परन्तु नई ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी (2005 का 7 वां

संस्करण) ने इसकी परिभाषा आपराधिक कृत्य या ऐसा कृत्य जो नैतिक या बड़ी गलती है, तथा कानून द्वारा सजा प्राप्त करने योग्य है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 ने दोष (offence) शब्द का प्रयोग, अपराध (बतपउम) के स्थान पर किया है। IPC की धारा 40 के अनुसार 'दोष (offence) ऐसा कृत्य है, जो इस संहिता के अनुसार सजा प्राप्त करने योग्य है। एक दोष (offence) दो प्रकार से होता है—किसी कृत्य के करने से या किसी कृत्य के न करने से। इसलिए ऐसे 'अपराध जो महिलाओं के विरुद्ध' हो या जिसमें 'महिलाएं पीड़ित हों उन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया (सिंह 2012 अपहरण, हत्या पत्नी उत्पीड़न बलात्कार तथा छेड़खानी आदि महिलाओं के प्रति अपराध के उदाहरण है।?

पुलिस रिसर्च ब्यूरो, दिल्ली द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध को दो श्रेणी में बांटा गया है— (i) इण्डियन पैनल कोड (IPC) के अन्तर्गत अपराध और (ii) विशेष कानून के दायरे में आने वाले अपराध देखें क्राइम इन इंडिया, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, दिल्ली 1994: 209। ब्यूरो द्वारा पहली श्रेणी में 7 व दूसरी श्रेणी में 4 तरह के अपराध चिह्नित किये गये। IPC के तहत ये सात अपराध हैं— बलात्कार, अपहरण एवं भगा ले जाना, दहेज के लिए हत्या, प्रताड़ना (मानसिक एवं शारीरिक), उत्पीड़न, छेड़छाड़ और 21 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ दुराग्रह। इसके अलावा ये चार अपराध भी स्थानीय व विशेष कानून के तहत आते हैं। ये हैं—सती प्रथा, दहेज प्रथा, महिलाओं का अश्लील चित्रण और अनैतिक देह व्यापार।

वे कौनसी महिलाएं हैं, जिन्हें उत्पीड़न किया जाता है? उनको उत्पीड़न करने वाले और हिंसा के अपराधकर्ता कौन लोग हैं? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मूल कारण क्या है। कुछ विद्वानों ने, जिन्होंने पाश्चात्य समाज में इन पहलुओं का अध्ययन किया है, इस

समस्या की व्याख्या के लिए 'व्यक्तित्व' उपागम और 'परिस्थिति' उपागम का उपयोग किया है। परन्तु इन दोनों उपागमों के कई बिन्दुओं को लेकर उनकी आलोचना हुई है।

(i) आपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार, अपहरण, हत्या.....

(ii) घरेलू हिंसा जैसे दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं और/या वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार.....

(iii) सामाजिक हिंसा जैसे पत्नी/पुत्रबधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना, अल्पवयस्क विधवा को सती होने लिए बाध्य करना, पुत्रबधू को और अधिक दहेज लाने के लिए सताना

यदि हम हम विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिये गए आंकड़ों का विश्लेषण करे तो पायेगे कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। एनसीआर (NCR) द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 1998 से 2011 के बीच 13 वर्षों में महिलाओं के प्रति अपराध में 74 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि की दर सबसे ज्यादा 140 प्रतिशत पर है, अपहरण 117 प्रतिशत, बलात्कार 60 प्रतिशत और छेड़छाड़ 40 प्रतिशत है। लगभग 30 प्रतिशत मामले पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के हैं (द संडे गार्जिन, 6 अप्रैल, 2013) इसी तरह लोकसभा सचिवालय (No.2/RN/Ref/2013) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध की कुल घटनायें (दोनों (जूस और रैस्स) जो 2007 में 1,85,312 थीं, 2011 में बढ़कर 2,28,650 हो गई। वर्ष 2012 में, यह संख्या 2,44,270 थी इस प्रकार वर्ष के दौरान 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अपराध के लिहाज से यह आंकड़ा इस प्रकार है—अपहरण (38,262) उनके शील (भंग) करने के इरादे के साथ महिलाओं पर हमला (45,351) महिलाओं के शील भंग के लिए किए गये अपमान (9,173), प्रति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (1,06,527) और विदेशों से लड़कियों को छल से/धोके से लाना (59) प्रतिशत के आधार पर हर वर्ष कुल अपराध

क्रमशः 1.6,1.9,0.4,4.5 और 0.0 हो रहे हैं भारतीय दंड संहिता (जब) के तहत। यह कहा जाता है कि भारत में हर 20 मिनट में एक बलात्कार हर 25 मिनट में छेड़छाड़, हर 40 मिनट में अपहरण और हर 4 घंटों में दहेज हत्या होती है। राजस्थान में भारतीय दंड संहिता मामलों का अनुपात राष्ट्रीय औसत के रूप में कुल अपराधों में महिलाओं के खिलाफ प्रतिबद्ध अधिक या कम ही रह गया है। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक वर्ष 2012 में राज्य में कुल 1,07,948 अपराधों के मामले सूचित किये गये जिसमें से 21,975 (या 12.81 प्रतिशत) महिलाओं के खिलाफ थे।

अपराधों के विरुद्ध महिला सैल (बॉब) और दिल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि और अन्य मामलों की संख्या में बढ़ोतरी से यह स्पष्ट है, कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि हुई है। शिकायतों की संख्या 2007 में 9853 से बढ़कर 2011 में 11,419 हो गई, लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि (सिफी न्यूज 16 दिसंबर 2012)। मामलों में यह वृद्धि जरूरी नहीं, कि बढ़ती रिपोर्टिंग की वजह से है, लेकिन यह केवल लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार में बढ़ती जागरूकता का संकेत है। उनकी सुरक्षा के लिए बने नये कानून में पीड़िता का विश्वास है, और इस तरह की संस्थाएं जैसे महिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और गैर-सरकारी संगठन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को पता है, कि विभिन्न कारणों की वजह से सभी मामलों सूचना नहीं दी जाती और न ही दर्ज होते हैं। घरेलू हिंसा जैसे पत्नी को पीटना या घर की महिलाओं के साथ जबरन अनाचार के मामलों की सूचना कभी नहीं दी जाती है। लेकिन संकलित मामलों की चर्चा करते हुए हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रकृति और विस्तार के बारे में कुछ अनुमान हो सकता है। हम छह व्यक्तिगत मामलों के विस्तार और लक्षणों का नीचे विश्लेषण करेंगे।

दहेज से संबंधित हत्याएं

दहेज हत्या या तो एक परेशान की गई पत्नी द्वारा आत्महत्या करके या लालची पति और ससुराल द्वारा हत्या करके होती है। जो वास्तव में माता-पिता, विधायकों, पुलिस, अदालतों और पूरे समाज के लिए बातचीत का कारण बन गयी हैं एक दिन भी नहीं

गुजरता जब हम एक महिला को परेशान होने, अत्याचार होने या मारे जाने का दहेज के कारण आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के बारे में न पढ़े। और अभी तक कितने आरोपी को दंडित किया गया (या सजा मिली है) दुल्हन जलाने के मामलों में कुछ हत्याओं को गिरफ्तार किया गया है, कुछ मुकदमा चलाया गया है, और आखिर में कुछ को सजा सुनायी गयी है। यद्यपि दहेज निषेधाज्ञा कानून, 1961 ने दहेज प्रथा पर रोक लगा दी है, परन्तु वास्व में कानून केवल यही स्वीकार करता है, कि समस्या विद्यमान है। वास्तविक रूप यह कभी सुनने में नहीं आता, कि किसी पति या उसके परिवार पर दहेज लेने के आग्रह को लेकर कोई मुकदमा चलाया गया हो। यदि कुछ हुआ है तो यह कि गत वर्षों में दहेज की मांग और उसके साथ-साथ दहेज को लेकर हत्याएं बढ़ी हैं। यदि एक सन्तुलित अनुमान लगाया जाए तो भारत में दहेज न देने अथवा पूरा नहीं देने के कारण प्रतिवर्ष हत्याओं की संख्या लगभग 5,000 मानी जा सकती है। भारत सरकार की मई 2000 में दी गयी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्तमान में हर 90 मिनट में एक दहेज से संबंधित हत्या होती, तथा एक दिन में 16 व एक वर्ष में लगभग 6,851 (द हिन्दुस्तान टाइम्स, मई 18,2000) 8,233 2012 में। अधिकांश दहेज हत्याएं पति के घर के एकान्त में और परिवारके सदस्यों की

मिलीभगत से हाते है इसलिए अदालतों प्रमाण के अभाव में दंडित न कर पाने की स्वीकार करती है। कभी-कभी पुलिस छानबीन करने में इतनी कठोर हो जाती है कि न्यायालय भी पुलिस अधिकारियों की कार्य-कुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करते है।

दहेज हत्याओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं जिनका मेरे आनुभविक अध्ययन से पता चला ये है : (1) मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्नवर्ग या उच्चवर्ग की स्त्रियों से अधिक हाती है: (2) लगभग 70 प्रतिशत पीड़ित 21.24 वर्ष आयु-समूह की होती है, अर्थात् कि वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, अपितु सामाजिक एवं भावात्मक रूप से भी परिपक्व होती है,

(3) यह समस्या निम्न जाति की समस्या की अपेक्षा उच्चजाति की अधिक है, (4) वास्तविक हत्या से पहले युवा वधू को कई प्रकार से सताया/अपमानित किया जाता है जो कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार के अव्यवस्थिति संरूप को दर्शाता है, (5) दहेज-हत्या के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण समाज वैज्ञानिक कारक अपराधी पर वातावरण का दबाव या सामाजिक तनाव है, जो उसके परिवार के आन्तरिक और बाह्य कारणों से उत्पन्न होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक हत्यारे का सत्तावादी व्यक्तित्व, प्रबल प्रकृति, और उसके व्यक्तित्व का असमायोजन है, (6) लड़की की शिक्षा के स्तर और दहेज के लिए की गयी उसकी हत्या में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता और (7) परिवार की रचना नव वधू के जलाने में निर्णायक भूमिका अदा करती है।

विधवाओं के विरुद्ध हिंसा

सब विधवाएं एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करतीं। एक विधवा ऐसी हो सकती है, जिसके कोई बच्चा न हो और जो अपने विवाह के एक या दो वर्षों में ही विधवा हो गई हो; या वह ऐसी हो सकती है, जो पांच से 10 वर्ष के पश्चात विधवा होती है और उसके एक या दो बच्चे पालने के लिए हों, या ऐसी हो जो 50 वर्ष की आयु से अधिक हो। यद्यपि इन तीनों श्रेणी की विधवाओं को सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक समंजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पहली और तीसरी श्रेणियों की विधवाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जबकी दूसरी श्रेणी की विधवाओं को अपने बच्चों के लिए पिता की भूमिका भी अदा करनी पड़ता है। इन दो किस्मों की विधवाओं का अपने पति के परिवार में इतना आदर-सत्कार पही होता जितना कि तीसरी किस्म का। वास्तव में जहां एक ओर परिवार के सदस्य विधवाओं की पहली दो श्रेणियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर तीसरी श्रेणी की विधवा अपने पुत्र के परिवार में मूल व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसका अपने पुत्र के बच्चों की देख-रेख का और काम पर जाने वाली पुत्रवधू की अनुपस्थिति में खाना पकाने का दायित्व सौंप दिया जाता है। विधवाओं की तीनों श्रेणियों की आत्मछवि और स्वाभिमान भी भिन्न होते हैं। एक विधवा की आर्थिक निर्भरता उसके स्वाभिमान और उसकी पहचान की भवना के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देती है। परिवार की भूमिकाओं में उनके सास-ससुर और परिवार के लिए अन्य सदस्यों द्वारा निम्न दर्जा प्रदान किए जाने से

उनका स्वाभिमान कम होता है। विधवा होने का कलंक ही अपने आप में एक स्त्री को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और उसका सम्मान अपनी ही दृष्टि में कम हो जाता है। यदि हम सब प्रकार की विधवाओं को ले तो हम कह सकते हैं कि विधवाओं के विरुद्ध हिंसा में पीटना, भावात्मक उपेक्षा/यातना, गाली गलौज करना लैंगिक दुर्व्यवहार संपत्ति में वैध हिस्से से वचन, और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार सम्मिलित है। विधवाओं के विरुद्ध हिंसा की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं: (1) युवा विधवाओं को अधेड़ विधवाओं की अपेक्षा अधिक अपमानित और तंग किया जाता है, और उनका शोषण और उत्पीड़न भी अधिक होता है; (2) साधारणतया, विधवाओं को अपने पति के व्यापार, हिसाब-किताब सर्टिफिकेटों, बीमे की पॉलिसियों और प्रतिभूतियों के बारे में नगण्य के बराबर जानकारी होती है और वे अपने परिवार (प्रजनन के) के बेईमान सदस्यों की धोखेबाजी के षड्यंत्रों की आसानी से शिकार हो जाती हैं और वे (सदस्य) इस प्रकार उनकी विरासत में मिली सम्पत्ति और जीवनबीमा के फायदों को हड़पने का प्रयास करते हैं; (3) हिंसा के अपराधकर्ता अधिकांशतया पति के परिवार के सदस्य होते हैं; (4) उत्पीड़न के तीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में— शक्ति, संपत्ति और कामवासना— संपत्ति मध्यवर्ग की विधवाओं के उत्पीड़न का निर्णायक कारक होता है, कामवासना निम्नवर्ग की विधवाओं के, और शक्ति मध्यवर्ग और निम्नवर्ग दोनों की विधवाओं के उत्पीड़न का निर्णायक कारक होता है; (5) यद्यपि सास का सत्तावादी व्यक्तित्व और पति के भाई-बहनो का असमंजस विधवा के उत्पीड़न में महत्वपूर्ण कारक होते हैं, फिर भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक विधवा की निष्क्रिय कायरता होता है; और (6) आयु, शिक्षा और वर्ग का विधवाओं के शोषण से महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंध दिखाई देता है, परन्तु परिवार की रचना और उसके आकार कोई परस्पर संबंध नहीं होते।

हिंसा के शिकार

यदि हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी प्रकारों को एक साथ ले तो हम पाएंगे कि हिंसा के साधारणतया शिकार वे महिलाएँ होती हैं :

जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं, जिनकी आत्मकछवि खराब होती है जो आत्मावमूल्यन से ग्रसित होती हैं, या वे जो अपराधकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा फलस्वरूप

भावात्मक रूप से समाप्त हो चुकी है, या वे जो परार्थवादी विवषता (altruistic powerlessness) से ग्रस्त हैं;

जे दबावपूर्ण परिवारिक स्थितियों में रहती है या ऐसे परिवारों में रहती है, जिन्हें समाजशास्त्रीय शब्दावली में 'सामान्य' परिवार नहीं कहा जा सकता। सामान्य परिवार वे हैं जो संचानात्मक रूप से पूर्ण होते हैं (दोनों माता-पिता जीवित हैं और साथ-साथ रह रहे हैं), अर्थिक रूप से निश्चिन्त हैं (सदस्यों की मूल और पूरक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं), प्रकार्यात्मक रूप से उपयुक्त (adequate) हैं (वे बिरले ही लड़ते हैं) और नैतिक रूप से नैष्टिक हैं;

- जिनमें सामाजिक परिपक्वता की या सामाजिक अन्तर-वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है, जिसके कारण उन्हें व्यहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है;
- जिनके पति/ससुराल वालों का विकृत (parhological) व्यक्तित्व है; और
- जिनके पति बहुधा मदिरापान करते हैं।

हिंसा के अपराधकर्ता

आमतौर पर महिलाएँ जिन पुरुषों द्वारा गाली और मार से पीड़ित हैं, उन्हें वे जानती हैं। यह एक अध्ययन द्वारा प्रामाणित है, कि इंग्लैंड (यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक, जोएना लिडेल) में भी 61 प्रतिषत महिलाएँ अपने स्वयं के परिवार के सदस्यों द्वारा और 39 प्रतिषत अजनबियों द्वारा गाली/मार से पीड़ित होती हैं दूसरी श्रेणी में 72 प्रतिषत महिलाएँ अपने पति के हाथों हिंसा की शिकार होती हैं, जिन्हें वे अच्छे से और वह भी उन स्थानों पर जहाँ वे खुद को सुरक्षित मानती हैं। भारत में भी विभिन्न राज्यों में पुलिस में दर्ज वैवाहिक हिंसा अपराधों से संकेत मिलता है, कि वैवाहिक घर एक महिला के लिए हमेशा सुरक्षित जगह नहीं है (इसका मतलब यह नहीं है कि एक औरत उसके घर की तुलना में बाहर सुरक्षित है)। पुरुषों का तर्क है, कि आज एक महिला पत्नी के परम्परागत मानकों का पालन नहीं करती। क्या वह एक महिला की कुछ स्तंत्रता की मांग करने पर उसके प्रति हिंसा करने को जायज ठहराने को प्रतिबिंबित नहीं करता। चाहे फिर वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हिंसा है? में इस तरह के पुरुषप्रधान तर्क को हो सकते हैं:

क्या हम आज के युग

- जो अपसादग्रस्त (depressed) होते हैं, जिनमें हीन- भावना होती है और आत्मसम्मान कम होता है;
- जिन्हें व्यक्तित्व के दोष होते हैं और जो मनोरोगी होते हैं;
- जिनके पास संसाधनों, प्रवीणताओं (skills) और प्रतिभाओं (talents) का अभाव होता है और जिनका व्यक्तित्व समाजवैज्ञानिक रूप से विकृत होता है
- जिनकी प्रकृति में मालिकानापन शक्कीपन, और प्रबलता
- जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं;
- जो बहुधा मदिरापान करते हैं।

हिंसा के प्रकार

- यदि हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण करें तो हम हिंसा के डह प्रकार बता सकते हैं;
- हिंसा जो धन – अभिमुख होती है;
- हिंसा जो कमजोर पर सत्ता प्राप्त करना चाहती है;
- हिंसा जिसका उद्देश्य भोग-विलास है;
- हिंसा जो अपराधकर्ता की विकृति के कारण होती है;
- हिंसा जो तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों के कारण होती है; और
- हिंसा जो पीड़ित प्रेरित

घरेलू हिंसा के मामलों वाले प्रमुख राज्य

कर्नाटक: एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में भारत में घरेलू हिंसा के सबसे अधिक मामले हैं, जिसमें 44% कर्नाटक दुर्भाग्य से और शर्मनाक रूप से पहले स्थान पर है। नहीं। एनएफएचएस 4 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या 20.6 प्रतिशत से बढ़ गई है। हालांकि अधिकांश मामले या तो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं या पीड़ित द्वारा

न्यायोचित ठहराए जाते हैं। एनएफएचएस 5 के अनुसार 18 वर्ष की आयु में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा 10.3% थी, जो एनएफएचएस 4 (2015–16) के अनुसार 11% थी।

बिहार: बिहार 18 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं के बीच वैवाहिक हिंसा के साथ दूसरे स्थान पर आता है, एनएफएचएस 4 के अनुसार 43.7% से 40% तक गिर गया, जबकि एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्ष की आयु में 8% महिलाओं ने यौन हिंसा का अनुभव किया। एनएफएचएस 4 के अनुसार 14.2% से घट रहा है।

मणिपुर: मणिपुर में घरेलू और पति-पत्नी की हिंसा के मामले एनएफएचएस 5 के अनुसार एनएफएचएस 4 के 53.2% से घटकर 39.6% हो गए हैं, लेकिन घरेलू शोषण के बढ़ने का एक भयानक कारक बना हुआ है। हालांकि, 18 साल की उम्र में महिलाओं के यौन शोषण के अनुभव 2015–16 में 14% से घटकर 2019–20 में 5.4% हो गए हैं।

तेलंगाना: तेलंगाना में घरेलू शोषण 2015–16 में 42.9% से घटकर 2019–20 में 36.9% हो गया है। दूसरी ओर यौन शोषण 2015–16 में 7.4% से घटकर 2019–20 में 5% हो गया है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण दर पर बना हुआ है।

असम: एनएफएचएस 5 के अनुसार असम 32% है और एनएफएचएस 4 के अनुसार 24.5 फीसदी से बढ़ गया है। इस वृद्धि ने कई लोगों में डर पैदा कर दिया है और कई लोगों को अपनी आवाज पर अंकुश लगाने की धमकी दी है। यहां तक कि यह वृद्धि 18 साल की उम्र में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के बढ़ने में भी देखी जा सकती है क्योंकि मामले 2015–16 में 5.8% से बढ़कर 2019–20 में 8% हो गए हैं।

आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश में घरेलू दुर्व्यवहार एनएफएचएस 4 के अनुसार 43.4% से एनएफएचएस के अनुसार 30% तक गिर गया है। आंध्र प्रदेश में यौन शोषण के मामले एनएफएचएस 5 के अनुसार एनएफएचएस 4 के अनुसार 6.8% से घटकर 3.7% हो गए हैं।

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में घरेलू शोषण 2019–20 में 33.1% से घटकर 2015–16 में 27% हो गया है। पश्चिम बंगाल में यौन शोषण दुर्भाग्य से 2015 में 8.9% से बढ़कर 2019–20 में 16 से 9.7% हो गया है।

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में घरेलू शोषण एनएफएचएस 4 के अनुसार 21.3 फीसदी से बढ़कर एनएफएचएस 5 में 25.2 फीसदी हो गया है। यह सपनों और अवसरों के केंद्र वाले शहर के लिए शर्म की बात है क्योंकि यौन हिंसा भी एनएफएचएस 4 के अनुसार 2.9% से बढ़कर 25.2 फीसदी हो गई है। एनएफएचएस 5 के अनुसार 6.2% ।

त्रिपुरा: त्रिपुरा में एनएफएचएस 4 के अनुसार 28.1% से एनएफएचएस 5 के अनुसार 20.7 फीसदी की भारी गिरावट देखी गई है। 18 पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले में त्रिपुरा एनएफएचएस 4 के अनुसार 10.2 फीसदी से घटकर एनएफएचएस 5 के अनुसार 7% हो गया है। (भारतीय राज्य घरेलू हिंसा)

लद्दाख: लद्दाख में घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है, एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट के अनुसार मामले 8.5% से बढ़कर 18.1% हो गए हैं। यौन शोषण के मामले में भी मामला 2015–16 में 1.2% से बढ़कर 2019–20 में 8.7% हो गयज़ं

घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों में सबसे कम प्रतिशत वाले राज्य:

जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत में घरेलू दुर्व्यवहार के सबसे अधिक मामलों को बताती है, यह घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों की सबसे कम संख्या भी बताती है। लक्षद्वीप, नागालैंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों का सबसे कम प्रतिशत क्रमशः 1.3%, 6.4%, 8.3p%, 8.3% और 9.6% है। हालांकि, मामलों का सबसे कम प्रतिशत एनएफएचएस 4 (2015–16) के लिए समान नहीं है।

उत्तर प्रदेश में हिंसा

डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, मार्च 2020 से घरेलू हिंसा के 4,300 से अधिक मामले राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में दर्ज किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली शीर्ष पर हैं। कथित तौर पर ब्दष-19 महामारी के प्रकोप के बाद से 1 मार्च से 18 सितंबर के बीच NCW को ईमेल, फोन और एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से 4,350 शिकायतें मिली हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) द्वारा संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश (968) से प्राप्त हुईं, उसके बाद दिल्ली में 784 शिकायतें आईं।

शिकायतों की उच्चतम संख्या विभिन्न राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को पंजीकृत आँकड़े

राज्य	शिकायतों की संख्या
यूपी	986
दिल्ली	784
महाराष्ट्र	458
बिहार	254
हरियाणा	229
कर्नाटक	137

महाराष्ट्र 458 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है जबकि बिहार (254) और हरियाणा (229) क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है। इस अवधि के दौरान कर्नाटक में 137 मामले सामने आए हैं।

अटकलें तेज हो गईं कि घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या दिखाई गई संख्या से अधिक हो सकती है क्योंकि कई मामले सामान्य रूप से रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य एजेंसियों जैसे पुलिस या राज्य महिला आयोग से संपर्क करते हैं।

प्रवृत्ति ने दिखाया कि अनलॉक अवधि के दौरान घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ीं।

जुलाई ने सबसे अधिक शिकायतें दर्ज कीं – 660 – उसके बाद जून (537) जब केंद्र ने चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया।

NCW ने अप्रैल में तालाबंदी के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी क्योंकि ज्यादातर लोग घर पर रह रहे थे या घर से काम कर रहे थे।

महिलाओं के खिलाफ अपराध पर घटनाएं

इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (राष्ट्रीय महिला आयोग) ने कहा कि उसे इस साल जुलाई में महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों की 2,914 शिकायतें मिलीं, जो नवंबर 2018 के बाद से सबसे अधिक है जब देश में MeToo आंदोलन अपने चरम पर था। एनसीडब्ल्यू के आंकड़ों के मुताबिक अकेले जुलाई में घरेलू हिंसा की 660 शिकायतें मिलीं। 2,914 शिकायतों में से 774 को गरिमा के साथ जीने के अधिकार के तहत प्राप्त हुई थी। गरिमा के साथ जीने का अधिकार खंड महिलाओं के भावनात्मक शोषण को ध्यान में रखता है।

जुलाई में प्राप्त शिकायतों की संख्या नवंबर 2018 के बाद से सबसे अधिक रही है – एक ऐसा समय जब देश में MeToo आंदोलन अपने चरम पर था। नवंबर 2018 में आयोग को 3,339 शिकायतें मिली थीं।

राज्यों में, उत्तर प्रदेश में कुल शिकायतों में से आधे से अधिक 1,461 और दिल्ली में 338 दर्ज की गईं। आंकड़ों से पता चला है कि घरेलू हिंसा श्रेणी के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के तहत 660 शिकायतों की दूसरी सबसे अधिक संख्या प्राप्त हुई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी ने कहा कि पिछले साल देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 371,503 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 405,326 और 2018 में 378,236 मामले दर्ज किए गए थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 की तुलना में शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में वर्ष 2020 में 8.3% की कमी आई, भले ही उस वर्ष औसतन हर दिन देश भर में लगभग 77 बलात्कार के मामले सामने आए। दिखाया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी की अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, पिछले साल देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 371,503 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 405,326 और 2018 में 378,236 मामले दर्ज किए गए थे।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश ऐसे मामलों की अधिकतम संख्या (49,385) के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल (36,439), राजस्थान (34,535), महाराष्ट्र (31,954) और मध्य प्रदेश (25,640) हैं।

भारत में विभिन्न राज्यों में सबसे अधिक मामले

राज्य	संख्या और नगद
यूपी	49,385
पश्चिम बंगाल	36,439
राजस्थान	34,535
महाराष्ट्र	31,954
मध्यप्रदेश	25,640

यौन हिंसा का अनुभव

कर्नाटक और बिहार में 40 से अधिक विवाहित महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा का सामना किया है

सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि 2015-16 में किए गए एनएफएचएस-4 की तुलना में देश के अधिकांश हिस्सों में पति-पत्नी की हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं के अनुपात में कमी आई है। एनएफएचएस-5 के पहले चरण में शामिल किए गए 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, यह देखा गया है कि कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, उन महिलाओं का अनुपात जिन्होंने कभी वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया (18 वर्ष की आयु की महिलाएं) 49) एनएफएचएस के पिछले संस्करणों की तुलना में कम हो गया है।

कर्नाटक में लगभग 44.4% महिलाएं, जहां यह प्रतिशत पिछले एक दशक में दोगुने से अधिक हो गया है, पति-पत्नी की हिंसा की शिकार थीं। बिहार दूसरा राज्य है जहां 40% से अधिक महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा की सूचना दी है। हालांकि, कर्नाटक के विपरीत, बिहार में पिछले एनएफएचएस सर्वेक्षणों की तुलना में वैवाहिक हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। एनएफएचएस-3 के दौरान, बिहार में 59 फीसदी विवाहित महिलाएं पति-पत्नी की

हिंसा की शिकार थीं, जो अब घटकर 40 फीसदी रह गई हैं। 30%से अधिक महिलाओं ने बताया कि उन्होंने मणिपुर, तेलंगाना, असम और आंध्र प्रदेश के प्रत्येक राज्य में वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में यह संख्या 25% से अधिक लेकिन 30%से कम थी। केरल, जम्मू और कश्मीर, गोवा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और लक्षद्वीप के प्रत्येक राज्य में, 10% से कम महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया।

महीने	घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा	सम्मान के साथ जीने का अधिकार	विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न महिलाओं के खिलाफ	साइबर अपराध	बलात्कार / बलात्कार का प्रयास	अन्य	कुल
Jan, 2019	133	266	87	39	78	702	1305
Feb, 2019	181	296	200	30	68	530	1305
March, 2019	148	269	204	22	63	338	1044
Apr, 2019	193	204	228	35	49	397	1106
May, 2019	266	234	397	49	150	621	1717
Jun, 2019	260	201	316	33	88	443	1341
Jul, 2019	391	288	361	43	115	620	1818
Aug, 2019	419	747	468	61	178	913	2786
Sep, 2019	255	819	468	40	168	629	2379

Oct,2019	252	584	391	35	129	494	1885
Nov,2019	243	434	368	35	137	425	1642
Dec,2019	219	352	275	37	116	403	1402
जनवरी 2020	271	374	267	32	142	376	1462
फरवरी 2020	302	436	221	21	112	332	1424
मार्च 2020	298	388	203	37	90	331	1347
अप्रैल 2020	315	238	62	55	12	118	800
मई 2020	393	472	159	73	54	352	1500
जून 2020	452	603	252	100	78	558	2043

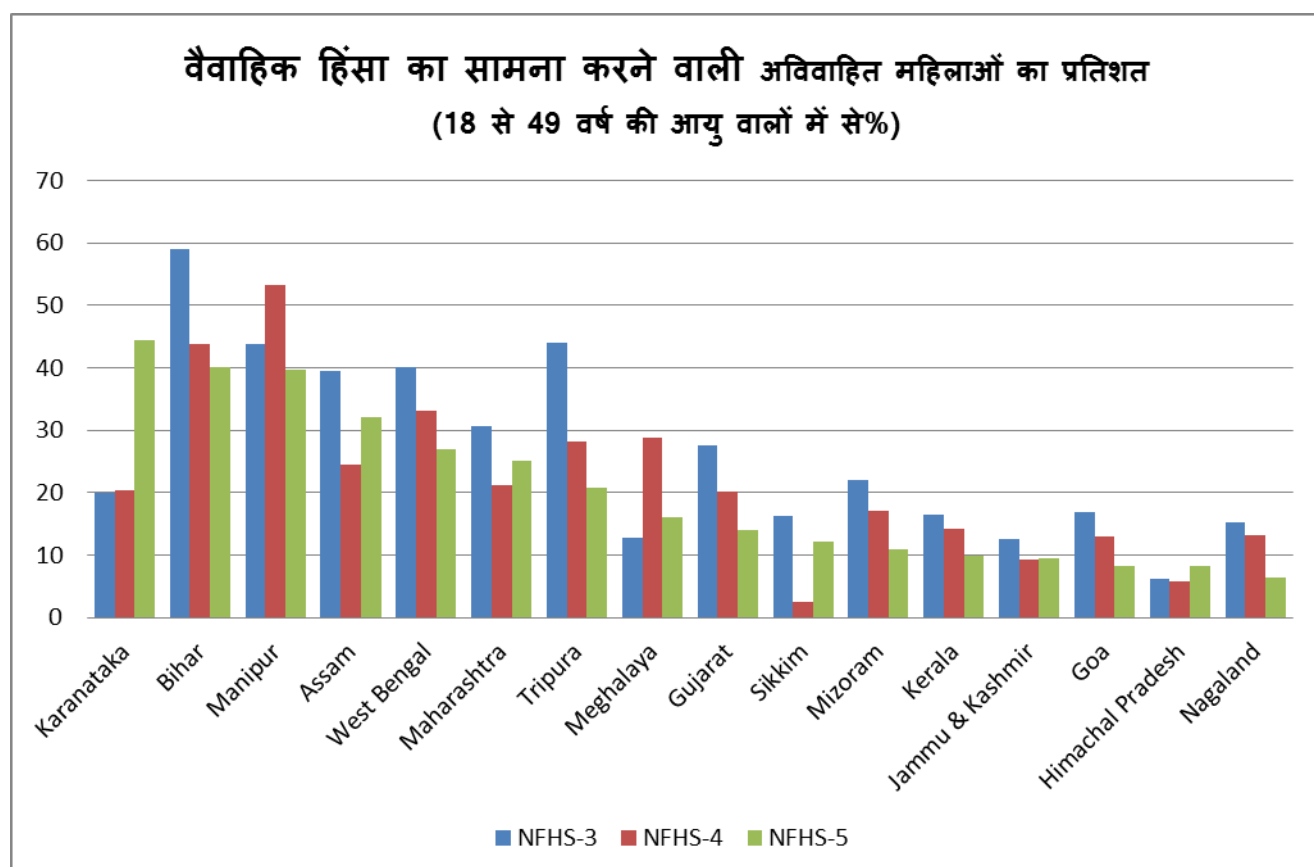
2019 –2020 के दौरान पंजीकृत चयनित शिकायतों की संख्या और प्रकृति

Column1	NFHS-3	NFHS-4	NFHS-5
कर्नाटक	20	20.6	44.4
विहार	59	48.7	40
मणिपुर	43.8	53.2	39.6
असम	39.4	24.5	32
पश्चिम बंगाल	40.1	33.1	27
महाराष्ट्र	30.7	21.3	25.2
त्रिपुर	44.1	28.1	20.7
मेघालय	12.8	28.8	16
गुजरात	27.5	20.2	14
सिक्किम	16.3	2.6	12.1
मिजोरम	22.1	17.1	10.9
केरल	16.4	14.3	9.9
जम्मू कश्मीर	12.6	9.4	9.6
गोवा	16.8	12.9	8.3
हिमाचल प्रदेश	6.2	5.9	8.3
नागालैण्ड	15.2	13.1	6.4

Source: National Commission for Women (NCW)

महिलाओं के खिलाफ अपराध, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत में दर्ज पाया गया है, चयनित प्रकार की हिंसा पर बढ़ा हुआ पाया जाता है, अर्थात्। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध और बलात्कार/बलात्कार का प्रयास। घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के संरक्षण के बारे में शिकायतें मार्च 2020 से जून 2020 तक लगातार बढ़ रही थीं। अप्रैल 2020 की तुलना में मई 2020 और जून 2020 के दौरान

गरिमा के साथ जीने के अधिकार में शिकायतों की संख्या उठाई गई। विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न –संबंधित भी अप्रैल 2020 के विपरीत, मई 2020 और जून 2020 के दौरान वृद्धि पाई गई। मार्च 2020 से जून 2020 तक महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध की शिकायतों में अप्रत्याशित वृद्धि हमेशा NCW में दर्ज की गई। बलात्कार में शिकायतों की संख्या में वृद्धि पाई गई। / अप्रैल 2020 की तुलना में मई 2020 और जून 2020 के दौरान बलात्कार का प्रयास।



Source: NFHS-5

दुनिया भर में तीन में से अधिक एक महिला अपने जीवनकाल में घरेलू हिंसा से प्रभावित होती है। भारत के नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएचएस) के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, इस आलेख में पुनर्जित और गौरव यह पाते हैं कि महिलाओं की शादी में एक वर्ष के देरी से कम गंभीर शारीरिक हिंसा की संभावना ८ प्रतिशत अंकों तक कम हो जाती है और गंभीर शारीरिक हिंसा ४ प्रतिशत अंकों तक। उपरोक्त अंक तालिका के आधार पर कर्नाटक, बिहार और मणिपुर में सबसे अधिक घरेलू हिंसक मामले एवं हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम मामले दर्ज हुए।

पंचम अध्याय

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और आपराधिक कानून के प्रावधानों के अलावा, भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 भारतीय संसद द्वारा समय-समय पर महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित कई विधायी अधिनियमों को रोकने के लिए पारित किया गया है। भारतीय समाज में ऐसा अपराध उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नलिखित हैं।

- 1- अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956
- 2- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- 3- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971
- 4- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
- 5- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987
- 6- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
- 7- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (सेक्स का निषेध .)
- 8- चयन) अधिनियम, 1994
- 9- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

भारत के विधि आयोग ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से, IPC] Cr-P-C में विभिन्न परिवर्तन किए हैं। और साक्ष्य कानून और बलात्कार पीड़ितों की कई समस्याओं को हल करने की कोशिश की है, लेकिन ये सिफारिशें अब तक पर्याप्त नहीं हैं। समाज के शिक्षित वर्ग को बलात्कार पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और मामले की सूचना तुरंत पुलिस अधिकारियों को देनी चाहिए। केवल कानून ही सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। सरकारी अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों,

स्वयंसेवी समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि को बलात्कार पीड़ितों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। बलात्कार के मामलों में पुलिस अधिकारियों के रवैये में बदलाव लाने की तत्काल आवश्यकता है। बलात्कार पीड़ितों के प्रति उनका सहानुभूतिपूर्ण रवैया होना चाहिए और पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

कानून-प्रवर्तन एजेंसियां यानी पुलिस और न्यायपालिका महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से बलात्कार के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कानून-प्रवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जब से अपराध की सूचना दी जाती है जब तक अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और दंडित किया जाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरणों जैसे, जांच, अभियोजन, परीक्षण और न्यायिक निर्णय शामिल हैं। पीड़ित को इन सभी चरणों में सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। कभी न खत्म होने वाले मुकदमों ने एक ऐसे परिदृश्य को भी जन्म दिया है जहां शिकायतकर्ता को सामाजिक दबाव के कारण अदालत के बाहर पीड़िता के साथ गुप्त रूप से समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कानून का पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है। सजा बढ़ाने का क्या फायदा जब दोषसिद्धि की संभावना ही दुर्लभ है?

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005: हाल में आई NCRB(राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो) की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ. इसके अलावा भी घर में होने वाले उत्पीड़न के मामले अक्सर जानकारी के बिना पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि आखिर घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कानून की धारा 498 । से अलग

घरेलू हिंसा अधिनियम (घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005), IPC की धारा 498 । से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह पीड़ित के संरक्षण को निश्चित करने का कानून है। जो दोषी को सजा नहीं देता परन्तु अगर वह दोषी इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए आदेशों की अवमानना करता है तो पारिवारिक मामलों को अर्द्ध आपराधिक मामलों की संज्ञा देते हुए आगे की प्रक्रिया में दोषी पक्ष को गिरफ्तार किया जा सकता है या वसूली की जा सकती है। और अगर पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मुकदमे की याचिका

दायर कर दे और दोष साबित हो जाए तो प्रतिवादी को अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है।

भारत में कई घरेलू हिंसा कानून हैं। सबसे शुरुआती कानून दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 था जिसने दहेज देने और प्राप्त करने का कार्य अपराध बना दिया। 1961 के कानून को मजबूत करने के प्रयास में, 1983 और 1986 में दो नई धाराओं, धारा 498। और धारा 304ठ को भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया। सबसे हालिया कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) 2005 है। घरेलू हिंसा को वयस्क द्वारा एक रिश्ते में दुरुपयोग की गई शक्ति दूसरे (महिला) को नियंत्रित करने को वर्णित किया जा सकता है। यह हिंसा और दुर्यवहार के अन्य रूपों के माध्यम से एक रिश्ते में नियंत्रण और भय की स्थापना करता है। यह हिंसा शारीरिक हमला, मनोवैज्ञानिक शोषण, सामाजिक शोषण, वित्तीय शोषण या यौन हमला का रूप ले सकती है, हालांकि घरेलू हिंसा की परिभाषा अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है।

हाल में ही एनसीआरबी द्वारा जारी आकड़े को देखे तो 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2018 से 7.3%की वृद्धि हुई (3,78,236 मामले)। आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामलों को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत दर्ज किया गया (30.9%), और अभी कोरोना वायरस महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामले में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा सदियों पुरानी घटना है। महिलाओं को हमेशा कमजोर, और शोषित होने की स्थिति में माना जाता था। हिंसा लंबे समय से महिलाओं के साथ होता है और पहले इसको स्वीकार किया जाता था।

2005 में स्थापित, घरेलू हिंसा अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) से महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू रिश्तों में महिलाओं को हिंसा से बचाने के उद्देश्य से सांसद द्वारा बनाया गया एक कानून है, के तहत सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएँ क्या हैं? घरेलू हिंसा की परिभाषा अच्छी तरह से लिखित और व्यापक और समग्र है। यह मानसिक, साथ ही शारीरिक शोषण को कवर करता है। उत्पीड़न, ज़बरदस्ती, स्वास्थ्य को नुकसान, सुरक्षा। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित के लिए विशिष्ट परिभाषाएँ हैं: शारीरिक शोषण: अधिनियम या आचरण के रूप

में परिभाषित किया गया है जो इस तरह की प्रकृति है कि शारीरिक दर्द, नुकसान, या जीवन के लिए खतरा, अंग या स्वास्थ्य या पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य या विकास को बिगाड़ने के लिए '। शारीरिक शोषण में मारपीट, आपराधिक धमकी और आपराधिक बल भी शामिल हैं।

जो किसी महिला की गरिमा को अपमानित, अपमानित, अपमानित करता है या अन्यथा उल्लंघन करता है। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग: किसी भी रूप का अपमान / उपहास, जिसमें एक पुरुष बच्चे की अक्षमता के संबंध में, साथ ही बार-बार धमकी भी शामिल है। आर्थिक दुर्यवहार: पीड़ित और उसके बच्चों के जीवित रहने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों से वंचित, किसी भी संपत्ति के निपटान के लिए, जिसमें पीड़ित के पास ब्याज / हिस्सेदारी और वित्तीय संसाधनों के निषेध प्रतिबंध शामिल हैं।

(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम) की अन्य प्रासंगिक विशेषताएं क्या हैं?

उपरोक्त परिभाषाओं के अलावा, निम्नलिखित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें अधिनियम कवर करता है। पीड़ित संसाधन अधिनियम के तहत, पीड़ितों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, परामर्श और आश्रय गृह के साथ-साथ आवश्यक होने पर कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

परामर्श: धारा 14 परामर्श, जैसा कि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित है, इसमें शामिल दोनों पक्षों को प्रदान किया जाना चाहिए, या जो भी पार्टी को आदेश दिया गया है, उसकी आवश्यकता होगी।

संरक्षण अधिकारी: धारा 9 अधिनियम के तहत, सरकार द्वारा हर जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो अधिमानतः महिलाएं होनी चाहिए और योग्य होनी चाहिए। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों में एक घरेलू घटना की रिपोर्ट दर्ज करना, आश्रय गृह, पीड़ितों के लिए चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता प्रदान करना, और यह सुनिश्चित करना कि उत्तरदाताओं के खिलाफ जारी किए गए संरक्षण आदेश जारी किए जाते हैं।

संरक्षण के आदेश: धारा 18 पीड़ित की सुरक्षा के लिए सुरक्षा आदेश प्रतिवादी के खिलाफ मुद्दे हो सकते हैं, और इसमें शामिल हैं जब वह हिंसा करता है, सहायता करता है या उसे रोक देता है, किसी भी जगह में प्रवेश करता है, जहां पीड़ित व्यक्ति उसके साथ संवाद करने का प्रयास करता है या पीड़ितों की संपत्ति के किसी भी रूप को प्रतिबंधित करता है। पीड़ित के हित के लोगों के लिए हिंसा।

निवास: धारा 19 मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों के निवास स्थान से प्रतिवादी को प्रतिबंधित करने का विकल्प चुन सकता है यदि उन्हें लगता है कि यह पीड़ित की सुरक्षा के लिए है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी पीड़ित को निवास स्थान से बेदखल नहीं कर सकता है।

मौद्रिक राहत: धारा 20 प्रतिवादी को नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित को राहत प्रदान करना है, जिसमें आय, चिकित्सा व्यय, विनाश, क्षति या हटाने, और पीड़ित और उसके बच्चों के रखरखाव से संपत्ति के नुकसान के कारण होने वाले किसी भी खर्च शामिल हैं।

बच्चों की हिरासत: धारा 21 यदि आवश्यक हो तो प्रतिवादी के अधिकारों का दौरा करने के साथ, बच्चों के हिरासत को आवश्यकतानुसार पीड़ित को प्रदान किया जाना चाहिए।

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के क्या लाभ हैं?

यह कानून CEDAW (महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन) के बाद एक कानून बनाया गया था 'घरेलू संबंध' की परिभाषा सभी प्रकार की घरेलू व्यवस्था को कवर करने के लिए पर्याप्त है; उदाहरण के लिए, लिव-इन रिलेशनशिप(जब युगल शादी नहीं करते हैं)। इसमें शामिल किए जाने के साथ-साथ ऐसे रिश्ते जो कपटपूर्ण या द्वेषपूर्ण की श्रेणी में आते हैं, एक अग्रणी कदम था। लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में, भरत मठ और ऑर्म्स बनाम विजया रेंगाथन और ओआरएस के मामले में पारित एक विशिष्ट निर्णय में, यह निर्णय लिया गया था कि लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर पैदा हुआ बच्चा संपत्ति (संपत्ति) का हकदार है। माता-पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति, लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं)। इसका मतलब है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला और उसके बच्चे को आर्थिक शोषण का खतरा नहीं हो सकता है। बेशक, हालांकि यह संपत्ति के स्वामित्व और हिंदू विवाह अधिनियम की अधिक

प्रासंगिकता है, लेकिन यह जानकर खुशी हो रही है कि जिन बच्चों के विवाह के संबंध नहीं हैं, वे संपत्ति के अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, अधिनियम में पति या पुरुष पार्टनर के पुरुष और महिला रिश्तेदारों (जो उन स्थितियों में मदद करते हैं, जहां परिवार के सदस्य पत्नी को परेशान करते हैं) द्वारा किए गए घरेलू हिंसा से राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त, "बच्चे" की परिभाषा भी पालक, दत्तक और सौतेले बच्चों की समावेशी है। प्रतिवादी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित को मुआवजा दे और वित्तीय संसाधनों को न काटे, और यह पीड़ित को न केवल हिंसा से बचाता है, बल्कि उसके हितों की भी रक्षा करता है। "साझा घर" की परिभाषा यह निर्दिष्ट करती है कि चाहे पीड़ित के पास कानूनी अधिकार / इक्विटी हो या नहीं; यदि उसने प्रतिवादी के साथ घर में निवास किया है, और वह उसके साथ हिंसक रहा है, तो प्रतिवादी अधिनियम के तहत उत्तरदायी है। इसका मतलब यह है कि भले ही उसके पास घर में कानूनी या वित्तीय हिस्सेदारी न हो, प्रतिवादी उसे बेदखल नहीं कर सकता। संरक्षण के आदेश अधिकांश उदाहरणों में शामिल हैं, जहां प्रतिवादी संभवतः पीड़ित का लाभ उठा सकता था, और फिर से केवल उस परिभाषा तक सीमित नहीं है। अंत में, कानून द्वारा जारी किए गए आदेश पीड़ित को सबूत के रूप में मुफ्त दिए जाने चाहिए। क्या सुधारा जा सकता है? अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक "स्पष्ट रूप से पीड़ित व्यक्ति" और "प्रतिवादी" की परिभाषाएं हैं; और घरेलू हिंसा के खिलाफ केवल महिलाओं के अधिकार अधिनियम में कैसे शामिल हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह अधिनियम महिलाओं को दिए गए अर्ध-आपराधिक या नागरिक उपचार प्रदान करता है, जिनकी आवश्यकता है एक विशेष सामाजिक संदर्भ है जिसमें भारत में घरेलू हिंसा होती है। न केवल महिलाएं घरेलू हिंसा पीड़ितों का एक उच्च अनुपात बनाती हैं, बल्कि कम राजनीतिक-सामाजिक और आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति के साथ मिलकर उन्हें अपमानजनक घरेलू संबंधों से बाहर निकलने के लिए कठिन है। एक मुद्दा जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, वह है कतार के रिश्ते। हालांकि एस। खुशबू बनाम के फैसले में अधिनियम में उसी का कोई विशिष्ट विवरण नहीं है। कन्नीमाला और अन्न।, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप केवल विषमलैंगिक संबंधों में प्रमुख उम्र के अविवाहित व्यक्तियों में ही स्वीकार्य है।

कार्यान्वयन में बाधाएं आ रही हैं

1) नियमों के वास्तविक कार्यान्वयन के साथ समस्याएं प्रतीत होती हैं। कई जिलों में, संरक्षण अधिकारियों को नियुक्त करने के बजाय, मौजूदा सरकारी अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाती है; और उसी से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं हैं। इसलिए वे अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकांश कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं, और इस वजह से पीड़ित अपने लाभ के लिए कानून का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। इसी तरह, आश्रय घरों के संबंध में, अधिनियम ने निर्दिष्ट किया कि पर्याप्त रूप से समझा जाना चाहिए। हालांकि, वास्तविक कार्यान्वयन में शोध से पता चला है कि कई जिलों में एक भी आश्रय गृह नहीं है।

2) हालांकि अधिनियम में कुछ दोष हैं, और कार्यान्वयन वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है; नीति अपने आप में काफी व्यावहारिक प्रतीत होती है। हां, यह समझना महत्वपूर्ण है कि पुरुषों को भी हिंसा का सामना करना पड़ता है। हां, अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू करना और सरकार को इस बात के लिए जवाबदेह रखना जरूरी है कि उन्होंने उसी के संबंध में बेहतर सुधार के उपाय क्यों नहीं किए हैं। हालांकि, यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि अधिनियम के समय (और अब भी), महिलाओं को न्याय तक पहुंच में आसानी प्रदान करने वाले कानून की शुरुआत करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसकी वजह यह है कि दहेज के कारण होने वाली मौतों में महिलाओं के खिलाफ उच्च और घरेलू और यौन हिंसा होती है। इस अधिनियम का उद्देश्य उन महिलाओं को एक सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान करना है जो घरेलू हिंसा का सामना करने के लिए नागरिक और अर्ध आपराधिक उपचार तक पहुंच प्राप्त करती हैं, और यह काफी हद तक ऐसा करने में सफल रही है। भारत जैसे देश में, जिसमें पितृसत्तात्मक समाज है तब ये कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम फलस्वरूप एक सराहनीय कानून है। यह महिलाओं के प्रति हिंसा की व्यापक किस्मों पर विचार और स्वीकार करता है। इस अधिनियम से पहले परिवार के अंदर घरेलू हिंसा की सभी विभिन्न स्थितियों को उन अपराधों के तहत निपटाया जाना था जो पीड़ित के लिंग के संबंध के अलावा आईपीसी में गठित हिंसा के संबंधित कृत्यों के तहत होते थे।

संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन—

(1) कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा, सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए, सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा।

5. पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य – कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट, जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है या जो घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है या जब घरेलू हिंसा की किसी घटना की रिपोर्ट उसको दी जाती है तो वह, व्यथित व्यक्ति को –

(क) इस अधिनियम के अधीन, किसी संरक्षण आदेश, धनीय राहत के लिए किसी आदेश, किसी अभिरक्षा आदेश, किसी निवास आदेश, किसी प्रतिकर आदेश या ऐसे एक आदेश से अधिक के रूप में किसी राहत को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की;

(ख) सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की;

(ग) संरक्षण प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की;

(घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की;

(ङ) जहाँ कहीं सुसंगत हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के उसके अधिकार की, जानकारी देगा :

परन्तु इस अधिनियम की किसी बात का किसी रीति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी

प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए, अपने कर्तव्य से अवमुक्त करती है।

6. आश्रय गृहों के कर्तव्य – यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से, उसको आश्रय उपलब्ध करने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा।

7. चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य – यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, किसी चिकित्सीय सुविधा के भारसाधक व्यक्ति से, उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो चिकित्सीय सुविधा का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित को उस चिकित्सीय सुविधा में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा।

8. संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति.– (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे और वह उन क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी, जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) ऐसे संरक्षण अधिकारी, जहाँ तक संभव हो, महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए।

(3) संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

9. संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य.– (1) संरक्षण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे (क) किसी मजिस्ट्रेट को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना;

(ख) किसी मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर और उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को उसकी प्रतियाँ अग्रेषित करके, जिसकी अधिकारिता

की स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है और उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं को उसकी प्रतियाँ अग्रेषित करके, किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, करना;

(ग) किसी मजिस्ट्रेट को, यदि व्यथित व्यक्ति, किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए, अनुतोष का दावा करने की वांछा करता हो, तो ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, आवेदन करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध करा

यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह का उपलब्ध कराना और किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए, अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को और उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को, जहाँ वह आश्रय गृह अवस्थित है, अग्रेषित करना;

(छ) यदि व्यथित व्यक्ति को शारीरिक क्षतियाँ हुई हैं तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, और उस क्षेत्र में, जहाँ घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, पुलिस थाने को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करना; —

(ज) यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनीय राहत के लिए आदेश का, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन और निष्पादन हो गया है;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो विहित किए जाएं, पालन करना।

(2) संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा और वह, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

10. सेवा प्रदाता.— (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी, जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा, महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अन्तर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी।

(2) किसी सेवा प्रदाता के पास, जो उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी —

(क) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता हो तो विहित रूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति, उस क्षेत्र में, जहाँ घरेलू हिंसा हुई है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना;

(ख) व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस संरक्षण अधिकारी को और पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर, घरेलू हिंसा हुई है, चिकित्सीय रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराया जाता है यदि वह ऐसी वांछा करती है और व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में सौंपे जाने की रिपोर्ट, उस पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है, अग्रेषित करना।

(3) इस अधिनियम के अधीन, घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों के या कृत्यों के निर्वहन में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला समझा जाता है या करने के लिए तात्पर्यित है, विरुद्ध न होगी।

11. सरकार के कर्तव्य.— केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि —

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों का नियमित अन्तरालों पर, लोक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है जिसके अन्तर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के जिनके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विवादकों पर समय-समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) विधि, गृह मामलों से संव्यवहार करने वाले उन सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों द्वारा जिनके अन्तर्गत घरेलू हिंसा के विवादकों को उठाने के लिए विधि व्यवस्था, स्वास्थ्य और मानव संसाधन भी हैं, उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है और उसका कालिक नियत पुनर्विलोकन किया जाता है;

(घ) इस अधिनियम के अधीन महिलाओं को सेवाओं के परिदान से सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकाल, जिसके अन्तर्गत न्यायालय तैयार करना और उन्हें प्रतिष्ठापित करना भी है।

षष्ठम – अध्याय

निषकर्ष एवं सुझाव

- इस प्रकार, कई शताब्दियों तक भारत में महिलाओं को देवी या देवी की तरह माना जाता था। हालांकि सती प्रथा थी, जिसमें विधवाएं स्वेच्छा से अपने दिवंगत पति की चिता में आत्मदाह कर लेती थीं, यह एक विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रथा थी जिसका अपनी पत्नियों पर पतियों के क्रूर आधिपत्य से कोई लेना-देना नहीं था; महिलाओं के कुछ वर्गों द्वारा सती प्रथा का अभ्यास किया जाता था, जो अपने पति की चिता पर मरना एक बड़ा सम्मान मानते थे।
- मध्यकाल के शुरुआती दौर में भी पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता थी। उदाहरण के लिए, जैन ननों को अपने पुरुष समकक्ष के समान ही स्वतंत्रता प्राप्त थी। महिला ट्रस्टी, पुजारी, परोपकारी, संगीतकार और विद्वान थे। हालांकि कुछ समय बाद, महिलाएं लगभग घर में बंद पालतू पालतू जानवरों की तरह थीं।
- महिलाओं की वह स्थिति कानून निर्माताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई। महिलाओं की उच्च स्थिति को प्रभावित करने वाली समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्या को देखते हुए, विधायिका ने ऐसी सभी आक्रामक गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया, जो समाज में महिलाओं की शांति और प्रगति के लिए हानिकारक पाए गए थे। महिलाओं को प्रभावित करने वाली समस्याएं ऐसी रही हैं कि दंडात्मक गलतियों से निपटने के लिए कानून बनाए गए हैं। सभी कानूनों का सर्वोच्च उद्देश्य महिलाओं की स्थिति की रक्षा करना और उनकी स्थिति में सुधार करना है। भारत में महिलाओं की स्थिति पर कानून देश की स्वतंत्रता के बाद ज्यादातर संवैधानिक विकास का परिणाम है।
- द्यत-कर्म से स्वतंत्रता प्राप्त करने पर भारत के लोगों ने एक संविधान अपनाया जिसे देश में एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- महिलाओं की स्थिति को संविधान के विजन और मिशन के अनुरूप लाने के लिए कानून बनाए गए हैं। जबकि घर पर संवैधानिक सिद्धांतों के बल ने विधायिका को

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर कानून का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया, महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में कई आंदोलन चल रहे थे। मानवाधिकार, लैंगिक न्याय, महिला अधिकारिता, भेदभाव के खिलाफ अधिकार इन सभी आंदोलनों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अवधारणा को एक नया मोड़ दिया और इस तरह की सभी अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियों से महिलाओं की रक्षा करना राज्य को एक जिम्मेदारी बना दिया। . दुनिया ने 'निजी यातना' को राज्य की जिम्मेदारी मानने की नई प्रवृत्ति देखी।

- इसी पृष्ठभूमि में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अवधारणा एक नए उपचार के रूप में सामने आई। नए आंदोलनों का एक विशेष संदेश पारंपरिक कानूनों में मौजूद नियमों और विनियमों को संशोधित करने वाला कानून बनाना था; नागरिक कानून को आपराधिक कानूनों के नियमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए एक पूरक उपकरण बनाने का आग्रह भी महसूस किया गया।
- इससे पहले भी अपराध के विशेष कानून के क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कवर करने के लिए कानून बनाया गया है, उदाहरण के लिए, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, सती निवारण अधिनियम, 1987 आयोग, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम)) अधिनियम 1994, आदि, और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।
- इन विधायी उपायों की एक विशेषता यह है कि यह एक मूल और साथ ही एक प्रक्रियात्मक कानून है। महिलाओं के संबंध में विशेष कानूनों द्वारा कवर किए गए अपराधों में अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम, 1971, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986, सती प्रथा शामिल हैं। रोकथाम अधिनियम, 1987 पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994, आदि।

इस तरह के कानून में सभी विधायी अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण कानून है जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 कहा जाता है।

- प्राथमिक विधान के अलावा राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित अधीनस्थ विधान के रूप में भी नियम हैं, जैसे सती आयोग (रोकथाम) नियम, 1998, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) नियम, 1987, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) नियम, 1996, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम, 2003 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006।
- घरेलू हिंसा को विधायिका द्वारा एक विशिष्ट आपराधिक अपराध के रूप में मान्यता दी गई थी, जब भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा, धारा 498-ए पेश की गई थी। यह धारा पति या उसके परिवार द्वारा विवाहित महिला के प्रति क्रूरता से संबंधित है। इसके बाद, न्यायालय ने चार प्रकार की क्रूरता को मान्यता दी, अर्थात्,
 - आचरण जो एक महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की संभावना है।
 - आचरण जिससे महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगने की संभावना हो
 - महिला या उसके रिश्तेदारों को कुछ संपत्ति देने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उत्पीड़न, या
 - उत्पीड़न क्योंकि महिला या उसके रिश्तेदार पैसे की मांग करने में असमर्थ हैं या कुछ संपत्ति नहीं देते हैं।

सजा तीन साल तक की कैद और जुर्माना है। क्रूरता के विरुद्ध शिकायत स्वयं व्यक्ति द्वारा दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। उसकी ओर से कोई रिश्तेदार भी शिकायत कर सकता है।

संसद ने एक कदम और आगे बढ़कर एक नया कानून बनाया जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 कहा जाता है। इस कानून के द्वारा, घरेलू हिंसा किसी भी रिश्ते में व्यवहार का एक पैटर्न है जिसका उपयोग किसी महिला पर शक्ति और नियंत्रण हासिल करने या बनाए रखने के लिए किया जाता है।

सुझाव

घरेलू हिंसा सभी सामाजिक—आर्थिक पृष्ठभूमि और शिक्षा स्तरों के लोगों को प्रभावित करती है। घरेलू हिंसा को आपराधिक न्याय प्रणाली से समन्वित और व्यवस्थित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

जबकि भारतीय दंड संहिता में धारा 498। जैसे नए प्रावधानों के रूप में कानून और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 नामक नए कानून में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण आपराधिक कानून सुधार हैं। लेकिन ये सुधार पर्याप्त नहीं हैं।

केवल किसी अधिनियम को पारित करने और उसे कानूनी कागज पर लिख देने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि उसका मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य सभी विभागों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि घरेलू हिंसा के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

नए अधिनियम की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं को सुरक्षित आवास का अधिकार है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 वैवाहिक और साझा घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे उसका घर में कोई कानूनी शीर्षक हो या नहीं। विवाहित महिलाओं की शांति सुनिश्चित करने के लिए यह एक बहुत अच्छा विकास है।

महिला के पति को "शांति बनाए रखने के बंधन" या "अच्छे व्यवहार के बंधन" को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के माध्यम से निष्पादित करने की नीति अपनाना आवश्यक है जो पति को घरेलू हिंसा को रोकने का आदेश देता है। पति को प्रतिभूतियां (अर्थात धन या संपत्ति) जमा करने के लिए भी कहा जा सकता है, यदि वह हिंसक कार्य करना जारी रखता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। जब किसी सुरक्षा आदेश के उल्लंघन पर पीड़ित को पुलिस से संपर्क किया जाता है, तो पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें एक समन्वित कानूनी दृष्टिकोण की ओर देखने की जरूरत है। केवल इस तरह के समन्वित और समग्र दृष्टिकोण से घरेलू हिंसा का सामना करने वाले व्यक्तियों को कानूनी व्यवस्था से सच्ची

राहत पाने में मदद मिलेगी। सभी मजिस्ट्रेटों, वकीलों और पुलिस कर्मियों के लिए घरेलू हिंसा पर जागरूकता कार्यक्रम / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अधिनियम के कार्यान्वयन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड। 2012,2013,2014,2015,2016।भारत में अपराध। 2012,2013,2014,2015,2016।
- भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 2015. प्रेस सूचना ब्यूरो। (ऑनलाइन) दिसंबर 18, 2015। (उद्धृत: 25 सितंबर 2016।) [http%@@pib-nic-पद@newsite@mbErel-asp\relid=133564A](http://pib-nic-पद@newsite@mbErel-asp\relid=133564A)
- सरकार, उत्तर प्रदेश। यूपी। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष। (ऑनलाइन) (उद्धृत: 7 जुलाई 2016।) ीजजच://डीपसांसलंद.नच.दपब. पद/उे/।
- भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 2015. प्रेस सूचना ब्यूरो। (ऑनलाइन) 24 अप्रैल 2015। (m)`r% 14 vxLr 2016A½ [http%@@pib-nic-in@newsite@PrintRelease-asp?relid=118661A](http://pib-nic-in@newsite@PrintRelease-asp?relid=118661A)
- 2012-[http%@@www-keralawomen-gov-inA\(v,uykbu\) vxLr 2012A](http://www-keralawomen-gov-inA(v,uykbu) vxLr 2012A)
- भारत सरकार, [ds- MsVk-gov-in](https://data-gov-in@catalog@crime&against&womenA)। (ऑनलाइन) (उद्धृत: 7 सितंबर 2016।) [https%@@data-gov-in@catalog@crime&against&womenA](https://data-gov-in@catalog@crime&against&womenA)
- एबट, पी., और विलियमसन, ई. (1999)। महिला, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा। जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, 8:1, 83–102.
- अहमद, एस., कोएनिग, एम.ए., और स्टीफेंसन, आर. (2006)। प्रसवकालीन और प्रारंभिक बाल्यावस्था मृत्यु दर पर घरेलू हिंसा के प्रभाव: उत्तर भारत से साक्ष्य। एम जे पब्लिक हेल्थ 2006, 96रू1423–8।
- एनी एल., जी. एंड. (1995)। घरेलू हिंसा: परिवार संरक्षण चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 19.
- ब्लाउ, एम. पी. (1964)। सामाजिक जीवन में विनिमय और शक्ति। न्यूयॉर्क–विले: समाजशास्त्र विभाग, शिकागो विश्वविद्यालय, आईएलय पी.352.

- दोबाश, आर.आर. (1992)। महिला, हिंसा और सामाजिक परिवर्तन। लंदन: टलेज.
- डटन, डीएम (1992)। बाद के चरण में पीड़ित महिलाओं का इलाज करना। स्वतंत्र अभ्यास में मनोचिकित्सा, 10 (1-2), 93-98।
- फगोट, बी.आई., और रीड, आर.ए. (1998)। पुरुष से महिला आक्रामकता के विकासात्मक निर्धारक। जीआर (सं।) में, अंतरंग संबंधों में हिंसा (पीपी। 91-105)। पीएमए पब्लिशिंग कार्पोरेशन
- हमीद, एस.बी. (2011)। घरेलू हिंसा से निपटने के तरीके पर ईसाई महिलाओं को परामर्श। विकलांगता, विकास और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 97-98।
- हेइज, एल.जे. (1994)। महिलाओं के खिलाफ हिंसा – द हिडन हेल्थ बर्डन। वाशिंगटन डीसी: विश्व बैंक चर्चा पत्र।
- हिंडिन, जे। (2002)। जोखिम में कौन है? फिलीपींस में अंतरंग साथी हिंसा से जुड़े कारक। सामाजिक विज्ञान और चिकित्सा, 1385-1399।
- मामन, एस। (2000)। एचआईवी और हिंसा का प्रतिच्छेदन: भविष्य के अनुसंधान और हस्तक्षेप के लिए दिशा-निर्देश। सामाजिक विज्ञान और चिकित्सा, वॉल्यूम। 50. पीपी. 459-478।
- मोनेम, ए., पेना, के.आर., एल्सबर्ग, एम.सी., और पर्सन, एल.ए. (2003)। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से शिशु और बाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है: निकारागुआ में एक केस-रेफरेंस स्टडी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बुलेटिन, 81: 10-6.
- मूनी, जे. (1994)। घरेलू हिंसा की व्यापकता और सामाजिक वितरणरू सिद्धांत और पद्धति का विश्लेषण। लंदनरू मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी
- मॉरिसन, ए.आर., और ऑरलैंडो, एम.बी. (1999)। घरेलू हिंसा की सामाजिक और आर्थिक लागत: चिली और निकारागुआ। वाशिंगटन डीसी: इंटरअमेरिकन डेवलपमेंट बैंक।
- नारायण, जी. (1996)। उत्तर प्रदेश, भारत में पुरुषों के बीच पारिवारिक हिंसा, लिंग और प्रजनन स्वास्थ्य व्यवहार। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय परिषद को प्रस्तुति। क्रिस्टल सिटी, वर्जीनिया। .

- नैश, जे। (1992)। नागोविसी के बीच कम घरेलू हिंसा से संबंधित कारक'। जे के डी ए काउंट्स, सेंक्शंस एंड सैंक्चुअरीज: कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन बीटिंग वाइव्स (पीपी. 99–109.) में। वेस्टव्यू: बोल्डर।
- पैन, एच.एस., नीडिंग, पी.एच., और ओश्लेरी, के.डी. (1994)। मध्यम और गंभीर पति-पत्नी की शारीरिक आक्रामकता की भविष्यवाणी करना। जर्नल ऑफ कंसल्टिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, 62, 975–981।
- पांडा, पी.के. (2004)। केरल में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा। तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत: स्थानीय स्तर के विकास पर केरल अनुसंधान कार्यक्रम, विकास अध्ययन केंद्र।
- पांडे, जी.के., दत्त, डी., और बनर्जी, बी. (2009)। घरेलू हिंसा में साथी और संबंध कारक: कलकत्ता, भारत में एक झुग्गी से महिलाओं का दृष्टिकोण। जर्नल ऑफ इंटरपर्सनल वायलेंस, 24.
- पूनाचा, वी. (1991)। महिला और हिंसा। बॉम्बे: एसएनडीटी विश्वविद्यालय
- राव, वी. (जुलाई 1993)। ग्रामीण भारत में दहेज मुद्रास्फीति: एक सांख्यिकीय जांच। जनसंख्या अध्ययन, वॉल्यूम। 47 (नंबर 2), पीपी 283–293।
- राव, जी., गीता, और एलेन, डब्ल्यू. (1998)। अंतर को पाटना: एचआईवी रोकथाम में लिंग और कामुकता को संबोधित करना। वाशिंगटन, डीसी: इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन।
- साहू, बी (2003)। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से घरेलू हिंसा का संदर्भ: उड़ीसा में एक स्लम समुदाय में एक अध्ययन। एम.फिल शोध प्रबंध।
- सेन, पी. (1998)। विकास अभ्यास और महिलाओं के खिलाफ हिंसा। लिंग और विकास, वॉल्यूम। 6, नहीं। 3, पीपी। 7–16.
- शिव कुमार, ए.के. वीमेन्स कैपेबिलिटीज एंड इन्फैंट मॉर्टेलिटी: लेसन्स फ्रॉम मणिपुर' इन एम. डी. गुप्ता, एल. चैन, और टी. कृष्णन (संस्करण)। भारत में महिलाओं का स्वास्थ्यरू जोखिम और भेद्यता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस: बॉम्बे, 55–94। बॉम्बे: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

- शोभा, एन. (2005 अप्रैल)। महिलाओं से संबंधित सामाजिक विधान का प्रभावी प्रवर्तन। बेंगलोर: सार्वजनिक नीति केंद्र, भारतीय प्रबंधन संस्थान।
- सनी, सी। (2005)। केरल में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का एक स्थितिजन्य विश्लेषण। कोच्चि: महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र, अनुसंधान संस्थान, सामाजिक विज्ञान राजगिरी कॉलेज।
- सनी, सी। (2003)। एर्नाकुलम जिले में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा। तिरुवनंतपुरम: सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज।
- वर्मा, डी., चंद्रा, पी.एस., थॉमस, टी., और केरी, एम.पी. (2007)। भारत में गर्भवती महिलाओं के बीच अंतरंग साथी हिंसा और यौन जबरदस्ती: अवसाद और अभिघातजन्य तनाव विकार के साथ संबंध। जे इफेक्ट डिऑर्डर 2007, 102:227&35A
- विसारिया, एल। (1999)। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा: ग्रामीण गुजरात से साक्ष्य। वाशिंगटन, डीसी: इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन।